» वर्ष: 01, अंक:14 » 16 से 31 जनवरी 2021, नि:शुल्क

न्यू इंडिया समाचार

नया भारत और नारी शक्ति

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना से शिक्षित हो रही छात्राएं और महिला सशक्तिकरण से स्वावलंबी हो रही महिलाएं

अभी तो सूरज उगा है

आसमान में सिर उठाकर
घने बादलों को चीरकर
रोशनी का संकल्प लें
अभी तो सूरज उगा है।

दृढ़ निश्चय के साथ चलकर
दृढ़ निश्चय के साथ चलकर
हर मुश्किल को पार कर
घोर अंधेरे को मिटाने
घोर अंधेरे को मिटाने
अभी तो सूरज उगा है।

विश्वास की लौ जलाकर
विश्वास की लौ जलाकर
विकास का दीपक लेकर
सपनों को साकार करने
अभी तो सूरज उगा है।

न अपना न पराया
न अपना न पराया
न मेरा न तेरा
सबका तेज बनकर
सबका तेज बनकर
अभी तो सूरज उगा है।

आग को समेटते
प्रकाश को बिखेरता
चलता और चलाता

अभी तो सूरज उगा है।
अभी तो सूरज उगा है।
अभी तो सूरज उगा है।

(वर्ष 2021 के आगमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कवि हृदय से निकली प्रेरणादायी और ओजस्वी पंक्तियां, जो भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए सभी देशवासियों के संकल्प और सामर्थ्य को उद्धृत करती हैं।

प्रधानमंत्री की आवाज में कविता सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें

न्यू इंडिया
समाचार
वर्ष: 01, अंक: 14 | 16 से 31 जनवरी 2021

संपादक
कुलदीप सिंह धतवालिया,
प्रधान महानिदेशक,
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

सलाहकार संपादक
संतोष कुमार
विनोद कुमार

सहायक सलाहकार संपादक
विभोर शर्मा

प्रकाशक और मुद्रक:
सत्येन्द्र प्रकाश,
महानिदेशक, बीओसी
(ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन)

मुद्रण: जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड, बी-278, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-20

संपर्क: ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन,सूचना भवन, द्वितीय तल,नई दिल्ली- 110003
ईमेल- response-nis@pib.gov.in

डिजाइनर
श्याम शंकर तिवारी

आर. एन. आई. नंबर
DELHIN/2020/78812

अंदर के पन्नों पर...

नए भारत के केंद्र में नारी शक्ति...

आवरण कथा | बीते छह साल में पीएम नरेंद्र मोदी सरकार की सोच के अनुरूप देश की आधी आबादी का हो रहा समग्र विकास। पेज 16-23

फ्लैगशिप योजना...
स्टार्टअप इंडिया:युवा सपनों की पहुंच अब आसमान पर
पेज 13-15

कोरोना से जंग...
जमीन पर उतरने लगा टीकाकरण का महाअभियान

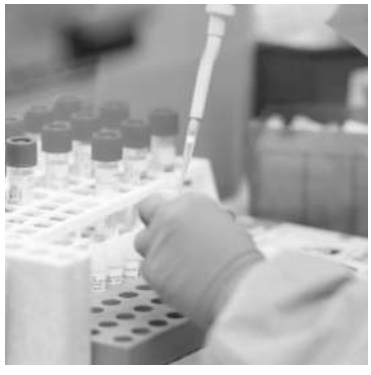

30 करोड़ लोगों को टीका लगाने की केंद्र सरकार की योजना जमीन पर उतारने की तैयारी अब पूरी। पेज 28-29

समाचार-सार
देश की प्रमुख खबरें। पेज 4-5

अब देश के संसाधनों पर सबका हक
मजहब की वजह से कोई पीछे न छूटे, बराबरी का हक | पेज 10-11

27 साल में तीसरा समझौता, अब कोई मांग नहीं बाकी
पूर्वोत्तर भारत शांति और विकास के पथ पर अग्रसर। पेज 12

अन्नदाता का सम्मान
कृषि सेक्टर कोरोना काल में भी प्रगति की ओर | पेज 24-25

लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय
14 सूत्रीय कार्यक्रम से खिलौना उद्योग करेगा तरक्की। पेज 26-27

भारत के साथ भारतीयता के दर्शन
कोरोना काल के बाद पर्यटन में अब नए अवसर। पेज 30-32

छात्रों के लिए केंद्र सरकार के अभूतपूर्व कदम
कैबिनेट के फैसले। पेज 33

देश के पहले परमवीर मेजर सोमनाथ शर्मा
परमगाथा परमवीचक्र विजेता की। पेज 34

भरोसा जीतने में सफल हो रही हैं योजनाएं
कहानी बदलते भारत की | पेज 35

" हम नये साल पर 'वोकल फॉर लोकल' का संकल्प लें"
मन की बात 2.0, 19वीं कड़ी। पेज 36

महानायक को नमन...

आजादी के 60 साल बाद पीएम मोदी के कार्यकाल में सार्वजनिक हुईं नेताजी से जुड़ी फाइलें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनसे जुड़े सभी स्थलों पर कार्यक्रमों को आयोजन कर रही केंद्र सरकार। पेज 6-9

संपादक की कलम से...

सादर नमस्कार।

आपका स्नेह हमें लगातार मिल रहा है और आपको भी हमेशा की तरह 'न्यू इंडिया समाचार' के नए अंक की प्रतीक्षा रहती होगी। यह साल वैक्सीन के रूप में बड़ी उम्मीद का सपना साकार करने वाला है। टीकाकरण के महाअभियान का खाका बना सरकार कदम बढ़ा चुकी है।

नए भारत में केंद्र सरकार की समग्र और दूरदृष्टि वाली ऐसी ही अनोखी सोच की मिसाल है- महिला सशक्तीकरण। इस साल 22 जनवरी को 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के छह साल पूरे हो रहे हैं, साथ ही 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस है। केंद्र सरकार के इस अभियान ने सामाजिक धारणाओं को तोड़ा है और "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।" की सोच अब भारतीय संस्कृति में एक बार फिर से साकार होती दिख रही है। आधी आबादी की आकांक्षाओं के अनुरूप बीते छह साल में केंद्र सरकार की योजनाओं का केंद्र महिला बनी है। नारी शक्ति भी शिक्षा, विज्ञान, आर्थिक जगत, स्वरोजगार, राजनीति, उद्यम, खेल समेत हर क्षेत्र में आसमान छू रही है। इस बार की आवरण कथा नारी शक्ति के सम्मान, स्वाभिमान और स्वावलंबन की कहानी बताती है कि नारी तू नारायणी की सोच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार किया है।

23 जनवरी को नेताजी सुभाषचंद्र बोस की भी जयंती है। आजादी के इस महानायक को मौजूदा सरकार ने सम्मान दिया और वर्षों से ताले में बंद दस्तावेज सार्वजनिक किए। इस अंक में विशेष रिपोर्ट के तौर पर नेताजी के जीवन और सरकार के प्रयास हैं और देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की प्रेरणा देती कहानी भी है।

हमेशा की तरह अपने विचार और सुझाव हमें साझा करते रहिए...

पता- ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन,
सूचना भवन, द्वितीय तल
नई दिल्ली- 110003

ईमेल- response-nis@pib.gov.in

कुलदीप

(कुलदीप सिंह धतवालिया)

आपकी बात...

भारत सरकार द्वारा देशहित में किए जा रहे कार्यों का सकारात्मक विश्लेषण इस पत्रिका में प्राप्त हो रहा है। कृषि सुधार कानूनों के बारे में सभी शंकाओं के बारे में जिस तरह से बताया गया है और स्थिति स्पष्ट की गई है, वह प्रशंसनीय है। इस अंक में महामना पं. मदनमोहन मालवीय जी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर पठनीय सामग्री भी नई पीढ़ी को प्रेरित करने वाली है। सम्पादकीय टीम को बधाई!

डॉ. भरत पाण्डेय, pandeydrbharatb@gmail.com

न्यू इंडिया समचार पत्रिका उत्साहवर्धक है, इस पत्रिका के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के विचार एवं योजनाएं सामने आ पाती हैं। मैं पत्रिका की नियमित पाठक बनाना चाहती हूं। कृप्या पत्रिका भेजने का कष्ट करें।
बहुत धन्यवाद।

कनिका जैन
रतलाम, मध्य प्रदेश

दिसंबर का दूसरा अंक मिला। 'उमंग' के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। ऐसी सभी जानकारी बहुत अच्छी हैं। साथ ही राष्ट्रपति के भाषणों का संग्रह सराहनीय है।
धन्यवाद!

माधव कुलकर्णी।
kulkarni3350@gmail.com

यह पत्रिका यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है मैं आप सभी लोगों का बहुत आभारी हूं।

ps9610022@gmail.com

न्यू इंडिया समाचार पत्र से महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो रही है। यह एक सराहनीय प्रयास है। सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं के साथ-साथ आम जन की समस्याओं, जरूरतों पर भी कॉलम नियमित रूप से शुरू हो। शख्सियत पर अच्छी सामग्री प्रकाशित की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद। सद्प्रयासों को नमन।
सादर।

राकेश छोकर
chhokarrakesh100@gmail.com

नए कृषि कानून के बारे में विस्तार से जानकारी, अटल की यादें, सौर ऊर्जा का बेहतर विकल्प, कोविड वैक्सीन की तैयारी, अर्थव्यवस्था की लगातार बेहतर होती स्थिति के बारे में दी गई जानकारी सराहनीय है।

kheemanandpenday1979@gmail.com

मैंने न्यू इंडिया समाचार को पढ़कर ये अनुभव किया कि इसमें ताज़ा खबरें और सामान्य ज्ञान के लेखों का श्रेष्ठ संग्रह है। सफल प्रयास के लिए आभार। ऐसे लेख और सामग्री भावी पाठक के लिए उपहार हैं।

अनीता मालवीय
anitaamalviya@gmail.com

महोदय मुझे हाल ही में डाक द्वारा न्यू इंडिया समचार पत्रिका मिली थी। वर्तमान परिदृश्य में बहुत उपयोगी यह पत्रिका शुरू करने के लिए बधाई। यह पत्रिका सभी लोगों के लिए उपयोगी और रचनात्मक है। इसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय समाचार और सामान्य ज्ञान की जानकारी दी गई है। हम पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हैं।

डॉ. चंदन बसु
outlineofindia@gmail.com

शेर और बाघ के बाद अब तेंदुओं की संख्या 60% बढ़ी

'सेव द टाइगर' जैसे अभियान की बदौलत जहां भारत में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, वहीं अब तेंदुओं की संख्या में 60 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की 'स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया रिपोर्ट-2018' के अनुसार भारत में अब तेंदुओं की संख्या 12,852 हो गई है। इससे पहले वर्ष 2014 में हुई गणना के अनुसार भारत में 7,910 तेंदुए थे। यानी केवल 4 साल में तेंदुओं की संख्या 60 फीसदी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसे ग्रेट न्यूज बताया है। पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 3421, कर्नाटक में 1783 और महाराष्ट्र में तेंदुओं की संख्या में 1690 की बढ़ोतरी हुई है। गणना के दौरान कुल 51,337 तस्वीरें ली गईं। सांख्यिकी विश्लेषणों के अधार पर टाइगर क्षेत्र में कुल 12,800 तेंदुओं की गणना की गई है। इस गणना में हिमालय के ऊंचाई क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र से लेकर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है।

टोल बूथ मुक्त होगा भारत, जीपीएस से कटेगा टोल

भारत में आने वाले समय में नेशनल हाईवे पर सफर करते समय वाहन चालकों को बार-बार टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि 2 साल में पूरे देश को टोल नाका मुक्त कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार एक नया जीपीएस-आधारित कलेक्शन सिस्टम तैयार किया जा रहा है। नए सिस्टम से देश में वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी। इसमें, वाहनों की आवाजाही के आधार पर टोल राशि सीधे व्यक्ति के बैंक खाते से काट ली जाएगी। इससे समय के साथ ईंधन की भी बचत होगी। टोल प्लाजा बनाने में लगने वाला खर्च भी बचेगा। अभी सभी कॉमर्शियल वाहन ट्रैकिंग सिस्टेम के साथ आ रहे हैं, वहीं पुराने वाहनों में जीपीएस लगाने के लिए केंद्र सरकार एक योजना लेकर आएगी। नई जीपीएस टेक्नोलॉजी से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टोल के जरिए आय 5 साल में 1,34,000 करोड़ तक बढ़ सकती है।

24 घंटे बिजली का अधिकार, तय वक्त से ज्यादा काटी तो मुआवजा

ईज ऑफ लिविंग के तहत आम आदमी के जीवन को आसान बनाने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अब देशभर के बिजली उपभोक्ताओं के हित में बिजली(अधिकार व उपभोक्ता) नियम 2020 को लागू किया गया है। सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली पाने का अधिकार दिया गया है। बिजली कंपनियां तय वक्त से ज्यादा कटौती करती हैं तो उन्हें उपभोक्ताओं को मुआवजा देना होगा। अगर बिजली कंपनियां समय पर सर्विस मुहैया नहीं करातीं तो उन्हें ग्राहकों को मुआवजा देना होगा। यह मुआवजा सीधे ग्राहकों के बैंक खाते में जमा होगा। मुआवजा तय करने का जिम्मा रेगुलेटरी कमीशन को सौंपा गया है। हालांकि, एग्रीकल्चर समेत कुछ खास तरह के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को कम सप्लाई मिलेगी। इसके साथ अब बिजली कंपनियों को मेट्रो शहरों में 7 दिन में नया कनेक्शन देना होगा। छोटे शहरों में यह अवधि 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन की होगी।

अमेरिका का प्रतिष्ठित 'लीजन ऑफ मेरिट' अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को

वैश्विक मंच पर आज भारत की बढ़ती भूमिका को दुनिया के सभी देशों ने स्वीकार किया है। अमेरिका के साथ भी भारत की रणनीतिक साझेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत हुई है। इसीलिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका का प्रतिष्ठित 'चीफ कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ मेरिट' पुरस्कार दिया गया है। अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने प्रधानमंत्री की ओर से हाल ही में यह पुरस्कार स्वीकार किया। अमेरिका की ओर से यह पुरस्कार केवल सरकार या राष्ट्र प्रमुख को दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को यह पुरस्कार उनके बेहतरीन नेतृत्व और दूरदृष्टि के लिए दिया गया, जिसने भारत को वैश्विक शक्ति के तौर पर उभरने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि यह संबंधों में सुधार के भारत और अमेरिका के लोगों के प्रयास को मान्यता है।

अब डिजिटल पेमेंट एप DakPay से घर बैठे मिलेगा लाभ

'आपका बैंक, आपके द्वारा' के मंत्र के साथ 1 सितंबर को शुरू हुए इंडिया पोस्ट पेमेंट ने अब डिजिटन अर्थव्यवस्था में योगदान के लिए डाक विभाग के साथ मिलकर 'डाकपे'(DakPay) एप लॉन्च किया है। इस एप के जरिए डिजिटल लेन-देन और आसान होगा। एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस एप को अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर यूपीआई की तर्ज पर डायरेक्ट मनी ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके जरिए किसी भी QR कोड को स्कैन कर इसके जरिए डिजिटल पेमेंट किया जा सकता है। इस एप के जरिए इंडिया पोस्ट पेमेंट के बैंक खाते के साथ डाक विभाग की सुविधाओं का लाभ भी अब घर बैठे ही मिलेगा।

कोरोना के बाद बढ़ी नौकरियां, ईपीएफओ ने अक्टूबर में जोड़े 11.55 लाख नए सदस्य

दुनियाभर में कोरोना महामारी के चलते नौकरियों पर सबसे बुरा असर पड़ा। लेकिन भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'जान है तो जहान है' के मंत्र के साथ न सिर्फ कोरोना से रिकवरी के मामलों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, 'बल्कि जान भी, जहान भी' के मंत्र के साथ अब उद्योग-व्यापार और नई नौकरियों के मामले में भी हमारी स्थिति बेहतर हुई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(ईपीएफओ) द्वारा जारी किए गए ताजा पेरोल के आंकड़े इसके गवाह हैं। अक्टूबर 2020 में ईपीएफओ के साथ 11.55 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। पिछले साल अक्टूबर माह में 7.39 लाख नए सदस्य जुड़े थे। इनमें सबसे ज्यादा संख्या 18 से 25 साल के बीच की उम्र वाले युवाओं की है, वहीं महिलाओं की संख्या 2.08 लाख है।

जीएसटी: दिसंबर महीने में रिकॉर्ड कलेक्शन, पहली बार 1.15 लाख करोड़ के पार

बीते साल में कोरोना की वजह समाज के हर तबके को नुकसान उठाना पड़ा, चाहे वह आम आदमी हो या उद्योग जगत। लेकिन जैसे ही पाबंदियां हटी और धीरे-धीरे आर्थिक हालात सुधरने लगे तो दिसंबर अर्थव्यवस्था ने भी राहत की सांस भरी। यही वजह है कि जीएसटी लागू होने के बाद से लेकर अब तक दिसंबर 2020 के दौरान जीएसटी संग्रह सबसे ज्यादा रहा और पहली बार जीएसटी संग्रह ने 1.15 लाख करोड़ के स्तर को पार किया। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, दिसंबर 2020 में 1,15,174 करोड़ रुपए के जीएसटी राजस्व की वसूली हुई। इससे पहले सबसे अधिक जीएसटी वसूली अप्रैल 2019 में 1,13,866 करोड़ रुपए की रही थी।

महानायक को नमन

अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या था? आप कहेंगे- पं. जवाहरलाल नेहरू। लेकिन क्या आपको भारत की पहली आजाद सरकार के बारे में पता है? भारत के आजाद होने से पहले 'पहली आजाद सरकार' का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। वो इसके प्रधानमंत्री भी थे। 21 अक्टूबर 2018 को आजाद हिंद सरकार के गठन की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया था। 23 जनवरी को उनकी 125वीं जयंती पर नेताजी से जुड़े सभी स्थलों पर इसके तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। नेताजी से जुड़े दस्तावेज को सार्वजनिक कर केंद्र सरकार ने आजादी के महानायक को दिया सम्मान...

“नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहादुरी जगजाहिर है। हम इस प्रतिभाशाली विद्वान, सैनिक और महान जन नेता की 125 वीं जयंती जल्द ही मनाने जा रहे हैं। आइए हम सभी इस विशेष मौके को भव्य तरीके से मनाएं।
– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री”

ओडिशा के कटक में 23 जनवरी 1897 को जानकीनाथ बोस ने अपनी डायरी में लिखा- “एक बेटे का जन्म दोपहर के समय हुआ।” पिता की इच्छा थी यह बेटा बड़ा हो कर आईसीएस अफसर बने। वर्ष 1920 में देश में चौथा स्थान पाकर बेटे ने उनकी यह इच्छा भी पूरी की। लेकिन मां भारती ने शायद उन्हें अपनी सेवा के लिए चुना था। इसीलिए तो 15-16 वर्ष की आयु में मां को पत्र लिखकर पूछने वाला बेटा कि मां क्या ये दुखिया भारतमाता का कोई एक भी पुत्र ऐसा नहीं है जो पूरी तरह अपने स्वार्थ को तिलांजलि देकर, अपना संपूर्ण जीवन भारत मां की सेवा में समर्पित कर दे? बोलो मां, हम कब तक सोते रहेंगे? वर्ष 1921 में आईसीएस से इस्तीफा दे कर वह देशबंधु चितरंजन दास की सलाह पर महात्मा गांधी से मिलने आ पहुंचे। यह बेटा एक महान स्वतंत्रता सेनानी और विचारक बन गया, जिसने अपना जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। ये देश उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानता है। महात्मा गांधी को नेताजी ने ही सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 1921 से 1941 तक 11 बार अंग्रेज सरकार ने उन्हें जेल में रखा था।

भारत की पहली आजाद सरकार की स्थापना और उसकी घोषणा सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को की थी। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री थे। लेफ्टिनेंट कर्नल ए. सी. चटर्जी आजाद हिंद सरकार के वित्त मंत्री,

एस ए अय्यर, प्रचार मंत्री और रास बिहारी बोस सलाहकार थे। उस वक्त 9 देशों की सरकारों ने सुभाष चंद्र बोस की सरकार को अपनी मान्यता दी थी। जापान ने 23 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार को मान्यता दी। उसके बाद जर्मनी, फिलीपींस, थाईलैंड, मंचूरिया, और क्रोएशिया ने भी आजाद हिंद सरकार को अपनी मान्यता दे दी। आजाद हिंद सरकार ने जापान सरकार के साथ मिलकर म्यांमार के रास्ते पूर्वोत्तर भारत में प्रवेश करने की योजना बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा (अब म्यांमार) की राजधानी रंगून को अपना हेडक्वार्टर बनाया, तब वहां जापान का कब्ज़ा था। 18 मार्च 1944 को सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने भारत की धरती पर कदम रखा था। और उस जगह को अब नागालैंड की राजधानी कोहिमा के नाम से जाना जाता है.

आजाद सरकार ने तिरंगा को तय किया था राष्ट्रीय ध्वज

आजाद हिंद सरकार ने ये तय किया कि तिरंगा झंडा भारत का राष्ट्रीय ध्वज होगा। रवींद्र नाथ टैगोर का जन-गण-मन भारत का राष्ट्रगान होगा और लोग एक दूसरे से अभिवादन के लिए जय हिंद का प्रयोग करेंगे । नेताजी ने 30 दिसंबर 1943 को अंडमान-निकोबार में पहली बार तिरंगा फहराया था।

नेताजी के सम्मान में पीएम ने परंपरा तोड़ लाल किले पर फहराया तिरंगा

2014 में केंद्र में सत्ता संभालने के बाद से केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र

नेताजी के सम्मान में केंद्र सरकार की ऐतिहासिक पहल

- लाल किले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक संग्रहालय स्थापित किया गया है। इसका आगे विस्तार किया जाना है। इसके अलावा केंद्र सरकार कोलकाता में भी नेताजी पर एक संग्रहालय शुरू करने जा रही है।
- वर्ष 2018 में, अंडमान और निकोबार के तीन द्वीपों- रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा गया।
- नेताजी के नाम पर वर्ष 2018 से हर सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार देने की शुरुआत भी की गई है।
- 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर नेताजी के तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहीं तिरंगा फहराकर नेताजी को याद किया था। जहां नेता जी ने पहली बार तिरंगा फहराया।

60 साल बाद सार्वजनिक हुई नेताजी से जुड़ी फाइलें

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विमान हादसे में कथित मृत्यु के बाद इसकी जांच के लिए तीन बार आयोग बनाए गए। देश की कमान संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर निर्णायक पहल की। प्रधानमंत्री ने 14 अक्टूबर 2015 को नेताजी के 35 सदस्यीय परिवार से मुलाकात कर कहा-"जो देश इतिहास भुला दे, वो इतिहास बनाने की शक्ति भी खो देता है। इतिहास का गला घोंटने की कोई वजह नहीं। इसलिए नेताजी से जुड़ी हुईं सभी फाइलें सरकार जारी करेगी।" इसी के साथ 4 दिसंबर 2015 को नेताजी से जुड़ीं 33 फाइलें राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंप दी गईं। 23 जनवरी 2016 को नेताजी के जन्म दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे जुड़ी हुई 100 फाइलों का पहला सेट जारी भी कर दिया। नेताजी से जुड़ी सभी फाइलों को डिजिटल रूम में वेबसाइट (www.netajipapers.gov.in) पर देखा जा सकता है।

125वीं जयंती पर पूरे वर्ष होंगे कार्यक्रम

नेताजी की 125वीं जयंती वर्ष समारोह की रूपरेखा तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गठित कमेटी में इतिहासकारों और बोस परिवार के सदस्यों के साथ-साथ आजाद हिंद फौज से जुड़े प्रमुख लोगों को भी शामिल किया गया है। 23 जनवरी को बोस की 125वीं जयंती से समारोहों की शुरुआत होगी, जो पूरे साल चलते रहेंगे। सुभाषचंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष समारोह के कार्यक्रम कोलकाता और दिल्ली के साथ-साथ देश-विदेश में उन सभी स्थानों पर आयोजित किये जाएंगे, जो नेताजी और आजाद हिंद फौज से संबंधित हैं। संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रह्लाद सिंह पटेल के अनुसार नेताजी की 125वीं जयंती पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में नेताजी की एक भव्य प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। 'एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम' के तहत पश्चिम बंगाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे।

बोस की विरासत को संरक्षित करने की दिशा में कई पहल की हैं। 21 अक्टूबर 2018 को आजाद हिंद सरकार के गठन की 75वीं वर्षगांठ पर नेताजी के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से तिरंगा फहराया था। यह पहली बार था, कि स्वतंत्रता दिवस के अलावा भारत के किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहाराया हो। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था- "ये वही लाल किला है, जहां पर victory parade का सपना नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने 75 वर्ष पूर्व देखा था। आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नेताजी ने ऐलान किया था कि इसी लाल किले पर एक दिन पूरी शान से तिरंगा लहराया जाएगा। आज भारत के सवा सौ करोड़ लोग नए भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसा नया भारत जिसकी कल्पना नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने भी की थी।" यही नहीं 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर नेताजी के तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहीं तिरंगा फहराकर नेताजी को याद किया था। ●

अब देश के संसाधनों पर सबका हक

मजहब की वजह से कोई पीछे न छूटे। सभी को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। इसी सोच को साकार करते हुए केंद्र सरकार अब देश के नागरिकों को बराबरी के हक के साथ राष्ट्र की प्रगति का भागीदार बना रही है ताकि भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से कदम बढाए

भारत अब उस दौर से निकलकर ऐसे समाज और राष्ट्र निर्माण के दौर में आगे बढ़ रहा है, जहां देश के संसाधनों पर किसी विशेष का नहीं, बल्कि हर नागरिक का हक बराबर है, सबके लिए समान अवसर उपलब्ध है। इसी सोच के साथ भारत को आत्मनिर्भरता की दिशा में ले जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में देश के दो बड़े विश्वविद्यालय- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और विश्व भारती के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। उन्होंने नए भारत के अपने संकल्प को कुछ इस तरह दोहराया, "आज देश भी उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के देश में हो रहे विकास का लाभ मिले। आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां का प्रत्येक नागरिक संविधान में मिले अधिकारों-भविष्य के प्रति निश्चिंत रहे। कोई मजहब की वजह से पीछे न छूटे। सभी को समान अवसर मिले और सभी अपने सपने पूरे करें। सबका साथ, सबका विकास

भेदभाव के बिना विकास यानी जो देश का है वो हर देशवासी का है

40 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खुले, जनधन योजना में

02 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पक्के घर मिले

8 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए

कोरोना के समय 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अन्न मिला

50 करोड़ लोगों को 5 लाख रु. का मुफ्त ईलाज संभव

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 1920 में एक कानून के तहत बनाया गया। इससे पहले यह मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, जिसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इस कॉलेज की स्थापना 1877 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। इसके तीन अन्य परिसर मल्लपुरम (केरल), मुर्शिदाबाद-जंगीपुर (पश्चिम बंगाल) और किशनगंज (बिहार) में हैं। 22 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। इस मौके पर डाक टिकट भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री के संबोधन के अहम बिंदु:

- नए भारत के विजन में यह कल्पना की गई है कि देश और समाज के विकास को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए।
- राजनीति इंतजार कर सकती है लेकिन समाज नहीं, इसी प्रकार गरीब चाहे किसी भी वर्ग से संबंधित हो, वह भी इंतजार नहीं कर सकता। हम समय को बर्बाद नहीं कर सकते, हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के मतभेदों को दूर रखा जाना चाहिए।
- देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां का प्रत्येक नागरिक, संविधान से मिले अपने अधिकारों को लेकर निश्चिंत रहे, अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत रहे।
- सरकार मुस्लिम बेटियों की शिक्षा और सशक्तीकरण पर ध्यान दे रही है। पिछले 6 साल में करीब 1 करोड़ मुस्लिम बेटियों को छात्रवृत्ति दी गई है।
- एक समय मुस्लिम बेटियों का स्कूल ड्रॉपआउट 70% था। स्वच्छ भारत मिशन के बाद यह 30% रह गया है।

विश्व-भारती विश्वविद्यालय

गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा 1921 में स्थापित विश्व-भारती देश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है। मई 1951 में संसद के एक अधिनियम द्वारा विश्व-भारती को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और 'राष्ट्रीय महत्व का संस्थान' घोषित किया गया था। प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 दिसंबर को विवि के शताब्दी समारोह पर जो कहा, उसके अहम बिंदु:

- विश्व भारती की 100 वर्ष की यात्रा बहुत विशेष है और यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। विश्व भारती के लिए गुरूदेव का विजन आत्मनिर्भर भारत का मूल तत्व भी है।
- कई प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए जारी वैचारिक आंदोलन को नई ऊर्जा, नई दिशा और नई ऊंचाई दी।
- स्वामी विवेकानंद में समर्पण, ज्ञान और कर्म तीनों समाहित थे। उन्होंने समर्पण के क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए कर्म को अभिव्यक्ति दी।
- मुझे खुशी है कि गुरूदेव द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में विश्व भारती, श्री निकेतन और शांति निकेतन निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारा देश पूरे विश्व में विश्व भारती से निकले संदेश को फैला रहा है।
- भारत के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए तो बंगाल की पीढ़ियों ने खुद को खपा दिया था। याद किजिए खुदीराम बोस को सिर्फ 18 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए। प्रफुल्ल चाकी 19 वर्ष की आयु में शहीद हो गए। बीना दास, सिर्फ 21 साल की उम्र में जेल भेज दी गई थीं। इन्हीं से प्रेरणा लेकर आत्मनिर्भर भारत के लिए जीना है और इस संकल्प को पूरा करना है।

और सबका विश्वास इसका मूल आधार है। देश की नीयत और नीतियों से यही संकल्प झलकता है।" विश्व भारती हो या बनारस हिंदू विवि, अलीगढ़ मुस्लिम विवि, मैसूर विवि, त्रिचि नेशनल कॉलेज, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, विलिंगडन कॉलेज, जामिया मिलिया इस्लामिया, लखनऊ विवि, पटना विवि, दिल्ली विवि, आंध्रा विवि, अन्नामलाई विवि, ऐसे अनेक संस्थान ऐसे कालखंड में स्थापित हुए हैं जहां से भारत की एक नई विद्वता का विकास हुआ। ऐसे में जब देश नए भारत के निर्माण की दिशा में अग्रसर है, इन विश्वविद्यालयों की महत्ता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। इन शिक्षण संस्थानों ने ही आजादी के लिए चल रहे वैचारिक आंदोलन को नई ऊर्जा, नई दिशा और नई ऊंचाई दी थी। ऐसे में सबके विकास के मूलमंत्र के साथ नरेंद्र मोदी सरकार भी नए भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अग्रसर है। ●

27 साल में तीसरा समझौता, अब कोई मांग नहीं बाकी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2020 में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बोडो संगठनों के साथ समझौते के बाद एक कार्यक्रम में कहा था, "हिंसा से न कभी कुछ हासिल हुआ है, ना आगे कुछ होने की संभावना है। हिंसा छोड़कर आगे आए हैं तो पूरे देश का आशीर्वाद आपके साथ है। उत्तर पूर्व, नक्सली क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर में हिंसा के मार्ग पर चलने वाले युवाओं से कहता हूं आइए, मेरे बोडो के नौजवानों से प्रेरणा लीजिए, मुख्यधारा में आइए। जीवन जीकर के जश्न मनाइए।" इसी सोच का असर है कि कभी उत्तर पूर्व की हिंसा और उग्रवाद में सालाना औसतन एक हजार से ज्यादा लोग जान गंवाते थे, अब लगभग पूरी शांति है और उग्रवाद समाप्ति की ओर है।

असम में 1993 से 2020 के बीच 27 साल में तीसरी बार बोडोलैंड की मांग वाले आंदोलन में जुड़े बोडो संगठनों के साथ समझौता हुआ। इससे पहले 1993 में पहला और 2003 में दूसरा समझौता हुआ था लेकिन कुछ ना कुछ मांग बाकी रहती थी। इस बार अलगाववादी संगठन नेशनल डोमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के सभी चार गुटों, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (आब्सू) के साथ केंद्र व राज्य सरकार का समझौता हुआ है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बोडोलैंड मूवमेंट से जुड़े लोगों को पांच दशक बाद सम्मान मिला है। सभी पक्षों ने मिलकर हिंसा के सिलसिले पर पूर्ण विराम लगाया है। आंदोलन से जुड़ी प्रत्येक मांग समाप्त हो गई है। पूर्ण विराम लग चुका है है। 1993 और 2003 में जो समझौता हुआ था, उसके बाद पूरी शांति स्थापित नहीं हो पाई। अब केंद्र, राज्य व बोडो संगठनों ने जिस सहमति पत्र पर साइन किया है, उसके बाद कोई मांग नहीं बची है। इसमें एकसाथ 1615 काडर ने समर्पण किया तो सरकार ने तीन साल के लिए 1500 करोड़ रुपए का विशेष विकास पैकेज घोषित किया है। हम बोडो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्या है बोडो समझौता

ऑल बोडोस स्टूडेंट्स यूनियन (आब्सू)ने 1972 में अलग बोडोलैंड राज्य की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया था। प्लेन ट्राइबल काउंसिल ऑफ असम(पीटीसीए) ने 1974 में बोडो आबादी वाले एक अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की मांग की। इन संगठनों ने कई बार हिंसक आंदोलन व बंद भी किए। उग्रवाद व जातीय हिंसा में 1991 के बाद बड़ी संख्या में काडर व अन्य लोगों की मौत हुई तो सुरक्षा कर्मी भी शहीद हुए।

अब क्या हुआ समाधान: करीब पांच दशक से बोडोलैंड की मांग कर रहे संगठनों ने अपनी सभी मांग का समाधान, विकास के लिए पैकेज सहित अन्य मांग पर सहमति जताकर जनवरी, 2020 में सभी संगठन, केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने समझौता हस्ताक्षर किया। इसके हिसाब से समझौते के पूर्व बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) का नाम बदलकर बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन(बीटीआर) किया गया। बीटीआर को अधिक अधिकार, सीटों की संख्या बढ़ाकर 40 से 60 करने के साथ कई नए जिले जोड़े गए। 30 जनवरी को 1615 काडरों ने हथियार के साथ समर्पण किया। ●

स्टार्टअप इंडिया

युवा सपनों की पहुंच अब आसमान तक

वर्ष 2014 में जब देश का मिजाज बदला तो पहली बार ऐसे शब्द सुनने में आए जो शायद इससे पहले बहुत कम लोगों ने सुने होंगे! स्टार्टअप एक ऐसा ही शब्द है। लेकिन इनोवेशन और इंक्यूबेशन के रास्ते युवा सपनों की तकदीर बदलने में विश्वास करने वाली केंद्र सरकार के प्रयासों की बदौलत अब 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप के साथ भारत इस मामले में दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत व्यवस्था है...

भारत की 65 फीसदी आबादी की औसत उम्र 35 साल है, जो दुनिया में सबसे युवा देश है। जरूरत है तो बस इन युवाओं के सपनों को सही रास्ता दिखाने की। इसी सोच और जज्बे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को लाल किले की प्राचीर से पहली बार 'स्टार्टअप इंडिया' की घोषणा की थी। 16 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा-"जो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए पैसा मायने नहीं रखता। जो करता है उसी को दिखता है कि क्या होने वाला है। हमारा सपना है देश का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने।"

"हम दो कारणों से इनोवेशन और इंक्यूबेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। पहला कारण यह है कि हम भारत की समस्याओं को सुलझाने के लिए आसान समाधान चाहते हैं। दूसरा कारण यह है कि हम भारत में रहते हुए पूरी दुनिया के लिए समाधान ढूंढ़ना चाहते हैं। भारत के अभिनव समाधान सबसे गरीब एवं सबसे वंचित लोगों के लिए भी होने चाहिए, चाहे वे किसी भी देश में रहते हों। –नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

रोजाना करीब 26 स्टार्टअप को मान्यता

- भारत में कर्नाटक एक ऐसी जगह है, जहां डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त फिनटेक स्टार्टअप की संख्या सबसे अधिक है।
- इनवेस्ट इंडिया के एक ट्वीट के अनुसार डीपीआईआईटी रोजाना करीब 26 स्टार्टअप को मान्यता दे रही है।
- सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश में कम से कम एक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है।

28,970

स्टार्टअप को मान्यता दी गई जनवरी 2016 से फरवरी 2020 के बीच

3.3

लाख लोगों को नौकरी (26,952 स्टार्टअप की रिपोर्ट के मुताबिक)

- इसमें 566 जिलों को कवर किया गया है।
- नौ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश) में सभी के 1000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं।
- महाराष्ट्र में महिला डायरेक्टरों वाले स्टार्टअप की संख्या सबसे ज्यादा है। साथ ही इस राज्य में स्टार्टअप की संख्या सबसे अधिक है।
- स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़े के मुताबिक, स्टार्टअप इंडिया हब पर अब तक 4,4,7,343 स्टार्टअप पंजीकृत है। डीपीआईआईटी ने लगभग 38,756 स्टार्टअप को मान्यता दी है। 264 स्टार्टअप को SIDBI फंड दिया है जबकि 221 स्टार्टअप ने टैक्स छूट का लाभ उठाया है।

कुतुकी
(स्नेहा सुंदरम)

– स्नेहा सुंदरम ने अपने पति भारत के साथ मिल कर कुतुकी नाम का एक स्टार्टअप शुरू किया है। स्नेहा का बनाया कुतुकी एप 100 फीसदी यानी पूर्ण रूप से भारतीय है और यह विशेष रूप से भारतीय बच्चों को ध्यान में रख कर बनाया गया है। इसमें कहानियां, कविताएं, कार्टून और चित्र कथाओं के माध्यम से बच्चों के सीखने के लिए बहुत कुछ नया होता है। विज्ञापन नहीं रहने के कारण बच्चों के लिए यह एप्प पूरी तरह से सुरक्षित है। ई- लर्निंग कैटेगरी में सरकार के आत्मनिर्भर भारत एप इनोवेशन चैलेंज में पुरस्कार जीतने के बाद यह एप सुर्खियों में आया। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 30 अगस्त 2020 को अपनी 'मन की बात' कार्यक्रम में भी इसका जिक्र किया।

"मैं स्टार्टअप, तकनीक और नवोन्मेषों को भारत के रूपांतरण और हमारे युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के रोमांचक एवं असरदार साधनों के तौर पर देखता हूं। – प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी"

साधारण शब्दों में कहें तो स्टार्टअप का अर्थ होता है नयी कंपनी को शुरू करना। ऐसी कम्पनियों को युवा उद्यमी स्वयं या दो तीन लोगों के साथ मिलकर शुरू करते है। शुरू करने वाला व्यक्ति ही कम्पनी में शुरुआती पूंजी लगाने के साथ कंपनी का संचालन भी करता है। ये कंपनी अपेक्षाकृत नये प्रोडक्ट्स या सेवाओं पर कार्य करती है, ऐसी सेवाएं जो उस समय बाजार में उपलब्ध नहीं होती है। हालांकि केंद्र सरकार के विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन (डीआईपीपी) के अनुसार "स्टार्टअप कंपनी वह कंपनी है जो भारत वर्ष में गत पांच वर्षों के अंदर रजिस्टर हुई है और जिसका टर्न ओवर 25 करोड़ से अधिक किसी भी वित्त वर्ष में अभी तक नहीं हुआ हो। यह कंपनी इनोवेशन, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, नए प्रोडक्ट्स

नाड़ी तरंगिनी
(अनिरूद्ध जोशी)

अनिरूद्ध जोशी स्टार्टअप इंडिया से मिली सहायता के कारण आज सफलता पूर्वक अपना बिजनेस चला रहे हैं। नाड़ी तरंगिनी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की मदद से नाड़ी परीक्षा करता है। यह किसी व्यक्ति की नाड़ी उसी तरह जांचता है जैसे एक वैद्य जांचता है। अनिरुद्ध जोशी का कहना है कि स्टार्टअप इंडिया से उन्हें बहुत लाभ मिला और उन्हें अपना व्यापार शुरू करने में मदद मिली। अपना स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए वह इस योजना को काफी कारगर और उपयोगी मानते हैं। इस स्टार्टअप को दो पुरस्कार मिले हैं। पहला – आयुष मंत्रालय की तरफ से सिल्वर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन आईटी और दूसरा लेक्सेस डिजायन अवार्ड (ज्यूरी च्वाइस) 2019।

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को कई तरह के लाभ

- **स्व प्रमाणन व टैक्स छूट:** तीन पर्यावरण और छह श्रम कानूनों के तहत नियमों का स्वयं पालन करना। लगातार 3 सालके लिए इनकम टैक्स में छूट और इन्वेस्टमेंट पर पूंजी में छूट।
- **कंपनी को बंद करने की सरल प्रक्रिया:** दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत 90 दिनों के भीतर।
- **पेटेंट एप्लीकेशन और आईपीआर सुरक्षा:** फास्ट ट्रैक सुविधा और पेटेंट भरने में 80% तक की छूट। एक विक्रेता के रूप में सरकार के साथ जुड़े और इएमडी एवं न्यूनतम आवश्यकताओं पर छूट का लाभ उठाएं।
- **SIDBI फंड्स ऑफ फंड्स :** भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) कोष का परिचालन करने वाली एजेंसी है। यह वैकल्पिक निवेश फंड के जरिए स्टार्टअप में निवेश के लिए फंड करती है।

सरकार कैसे देगी मदद

आपका बिजनेस आइडिया अगर पसंद आया तो सरकार जरूरी सुविधाएं देती हैं। साथ ही सरकार फंडिंग की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। इसके लिए www.startupindia.gov.in पर जानकारी हासिल की जा सकती है। स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए किसी भी इकाई को आवेदन करना होगा और डीआईपीपी द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त करनी होगी।

स्टार्टअप इंडिया के तहत किसे स्टार्टअप माना जाएगा ?

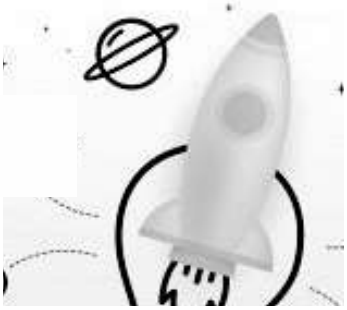

- इसे भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में इन्कॉर्पोरेट किया गया है या वह पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लायबलिटी पार्टनरशिप के रूप में रजिस्टर्ड है। अगर इन्कॉर्पोरेशन / रजिस्ट्रेशन के बाद से किसी भी फाइनेंशियल वर्ष के लिए इसका कारोबार 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हुआ है।
- अगर यह प्रॉडक्ट्स या प्रोसेस या सेवाओं के इनोवेशन, विकास या सुधार की दिशा में काम कर रहा है, या अगर यह रोजगार सृजन या धन कमाने की उच्च क्षमता वाला एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल है। हालांकि, किसी बिजनेस में टूट से या इसके री कंस्ट्रक्शन से बनी संस्था को 'स्टार्टअप' नहीं माना जाता है।

का व्यवसायीकरण, टेक्नोलॉजी आधारित सेवा अथवा बौद्धिक संपदा की दिशा में कार्य कर रही हो, ऐसी अपेक्षा की जाती है।" स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से सरकार इन नए और छोटे-छोटे स्टार्टअप न केवल वित्तीय सहायत, उचित मंच और प्रोत्साहन देती है तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर जैसे कार्यक्रम के जरिए इन्हें चुनौतीपूर्ण माहौल में तरक्की करने का हुनर भी सिखाया जाता है। नए स्टार्टअप के माध्यम से आज लाखों युवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार भी पा रहे हैं। ●

नए भारत के केंद्र में नारी शक्ति

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः।।

अर्थात् जहां पर स्त्रियों की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। जहां पर ऐसा नहीं होता है वहां पर सभी कार्य निष्फल होते हैं। भारतीय संस्कृति में नारी सम्मान की संपूर्णता महज इस श्लोक से ही स्पष्ट होती है। ऐसे में 'न्यू इंडिया' का सपना आधी आबादी की मजबूती के बिना अधूरा है। महिला शक्ति की यही आकांक्षा बीते छह साल में केंद्र सरकार की सोच और योजनाओं का केंद्र बना है शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, उद्यम, खेल समेत हर क्षेत्र में महिला शक्ति आज छू रही है आसमान

हमारा मंत्र होना चाहिए- 'बेटा बेटी एक समान' "आइए कन्या के जन्म का उत्सव मनाएं। हमें अपनी बेटियों पर बेटों की तरह ही गर्व होना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी बेटी के जन्मोत्सव पर आप पांच पेड़ लगाएं।
नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

भारत का प्रधानमंत्री एक भिक्षुक बनकर आपसे बेटियों की जिंदगी की भीख मांग रहा है। बेटियों को अपने परिवार का गर्व मानें, राष्ट्र का सम्मान मानें। आप देखिए इस असंतुलन से हम बहुत तेजी से बाहर आ सकते हैं। बेटा और बेटी दोनों वो पंख है जिसके बिना जीवन की ऊंचाईयों को पाने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए ऊंची उड़ान भरनी है तो सपनों को बेटे और बेटी दोनों पंख चाहिए तभी तो सपने पूरे होंगे।"

छह साल पहले 22 जनवरी को शीर्ष नेतृत्व के स्तर से बेटियों की जिंदगी को लेकर भीख मांगना महिला केंद्रित नए भारत के निर्माण की दिशा में एक ऐसा संकल्प था जो राजनैतिक नफा-नुक्सान की परवाह किए बिना समाज की संकीर्ण सोच को झकझोर रहा था। नारी शक्ति के बिना न्यू इंडिया की संकल्पना कतई नहीं की जा सकती। इसी सोच को साकार करते हुए केंद्र सरकार ने लगातार महिलाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप कदम उठाने शुरू किए।

सरकार के अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि आज राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व हो या सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल उड़ाना या मोर्चे पर दुश्मनों से मुकाबला करना या खेल जगत में दुनिया में देश का नाम रोशन करना या फिर स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठाकर बराबरी के साथ देश को आर्थिक मजबूती देना, महिला शक्ति सिर्फ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल रहीं बल्कि कहीं आगे निकल राष्ट्र का अभिमान बन रही हैं। महिलाओं ने अपनी अद्भूत क्षमता से यह साबित कर दिखाया है कि अगर उन्हें समान अवसर मिले तो सिर्फ घर ही नहीं, एक समृद्ध, गौरवशाली राष्ट्र का भी निर्माण कर सकती हैं। ऐसे में जब देश 22 जनवरी को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना की छठी सालगिरह और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहा है, तो यह बात किसी से छुपी नहीं है कि नारी शक्ति के इस अभिमान की वजह है- केंद्र सरकार की महिला केंद्रित एक समग्र सोच, जिसे साकार करने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।

परंपराएं तोड़तीं महिलाएं

महिला सशक्तीकरण किसी भी समृद्ध राष्ट्र और राजनीति की चाबी है। यही वजह है कि महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रही हैं। मिलिट्री, पुलिस, सशस्त्र बल में स्थायी कमीशन और राजनैतिक क्षेत्र में महिलाएं अपने नेतृत्व से

स्टैंड अप महिला, स्टैंड अप इंडिया

कभी महिलाओं को आर्थिक रूप से बोझ मानने वाली धारणाएं अब टूट रही हैं। केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना की वजह से आज 10 लाख से 1 करोड़ रु. तक का ऋण लेकर स्टार्ट अप के क्षेत्र में महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। अप्रैल 2020 तक देश में 76,451 महिला उद्यमियों को 17 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा ऋण दिया जा चुका है। परंपराओं को तोड़ती हुई महिलाएं एमसएसएमई के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में यह सुनिश्चित किया है कि 3 फीसदी खरीद महिला नेतृत्व वाली सूक्ष्म, लघु, मझोले (एमएसएमई) से होगी। इसके लिए 8 हजार से ज्यादा महिला उद्यमियों ने गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल पर पंजीकृत करा रखा है। महिलाओं के लिए खास तौर से इस ई-प्लेटफॉर्म पर 'वोमेनिया' और 'स्वायत्त' फीचर की सुविधा दी है। मुद्रा लोन योजना के तहत भी लाभ उठाने वालों में 70 फीसदी महिला समूह है। ग्रामीण भारत में 63 लाख के करीब स्वसहायता समूहों को राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत सहायता दी गई है, जो गरीबी और परिवार को अच्छा जीवन स्तर देने में जुटी हैं। हुनर-ई हाट में 32 हजार से ज्यादा महिला उद्यमी और स्वसहायता समूह पंजीकृत है जो 7 हजार से ज्यादा उत्पाद इस माध्यम से बेच रही हैं।

इनसे सीखिए जीतने का हुनर...

ग्रीन बायोटेक इको सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड की सह संस्थापक गीताशोरी युमनाम और डॉ. असेम सुंदरी देवी मणिपुर के इंफाल से हैं। वह कृषि खाद्य प्रसंस्करण और वानिकी की A2 श्रेणी की राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार 2019 की विजेता हैं। इन दोनों ने राज्य में जैविक आधारित कंपनी लगाने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी कंपनी जैव उर्वरकों और जैव कीटनाशकों, एक्वाकल्चर, पशुपालन और पर्यावरण प्रबंधन के साथ-साथ किसानों को निशुल्क परामर्श देने का काम करती है। उनकी कंपनी ने 25 महिलाओं को नौकरी भी दी है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है।

अर्ली फूडस प्राइवेट लिमिटेड के सह संस्थापक शालिनी संतोष कुमार और विजयलक्ष्मी नागराज महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। वे महिला उद्यमी के A1 श्रेणी में राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार 2019 की विजेता हैं। शालिनी संतोष कुमार ने अपनी मां के साथ मिल कर अपने घर पर एक छोटे से कमरे से अर्ली फूडस की शुरूआत की। जब शालिनी ने काम शुरू किया तब वह सात साल के एक बच्चे की मां थी। उनकी कंपनी, अर्ली फूडस प्राइवेट लिमिटेड एक जैविक खादय कंपनी है जो बच्चों और नई माताओं के लिए 25 से अधिक बाजरा आधारित पोर्रिज और स्नैक्स का निर्माण करती है। आज इस कंपनी को प्रति माह 15000 से अधिक ऑर्डर मिल रहा है।

सबको चुनौती देने में सक्षम हो रही हैं। जनवरी 2016 में केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ, सीआईएसएफ में सिपाही पद पर 33 फीसदी महिला आरक्षण अनिवार्य किया। यह ऐसा कदम है जो सुरक्षा बलों में महिलाओं के प्रति सोच को बदलने वाला है। 2019 के आम चुनाव में पहली बार रिकॉर्ड 78 महिलाएं सांसद चुनकर आई हैं तो पंचायती राज व्यवस्था में 46 फीसदी महिलाएं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

स्वस्थ महिला, समृद्ध परिवार

घर में कोई पुरूष बीमार होता है तो महिला दोहरी जिम्मेदारी को बखूबी संभाल लेती हैं। लेकिन महिला बीमार हो जाती हैं तो कुछ समय के लिए घर अस्त-व्यस्त हो जाता है क्योंकि महिलाएं समाज के साथ-साथ अपने परिवार की धुरी होती हैं। ऐसे में महिलाओं के स्वास्थ्य को सरकार ने 2014 से ही प्राथमिकता में रखा है। मातृत्व और शिशु सुरक्षा के लिए

आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में नई पहल

70% महिलाएं

मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को व्यापार के लिए 50 हजार से 10 लाख रुपये तक ऋण देने की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत लाभार्थियों में 70% महिलाएं हैं।

- महिला आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 6 करोड़ 60 लाख से अधिक महिलाओं को स्वसहायता समूहों से जोड़ा गया।
- प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 22 करोड़ से अधिक महिलाओं के बैंक खाते खोले गए। कोरोना काल में लॉकडाउन के समय 500-500 रुपये तीन किस्तों में इन्हीं खातों में भेजे गए।
- स्टैंड-अप इंडिया के अंतर्गत महिलाओं को अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए हर बैंक शाखा को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के ऋण कम से कम एक महिला को उपलब्ध कराने का नियम बनाया गया है।
- केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से देश की बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने का कार्य किया है। योजना के अंतर्गत 0-10 साल की कन्याओं के खाते डाकघर में खोले जा रहे हैं। इन खातों में जमा राशि पर 8.1 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज दिया जा रहा है।

26.75

लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग दी गई है। महिलाओं के आईटीआई में सालाना नामांकन में 97% की वृद्धि हुई है।

तीनों सेनाओं में पहली बार महिलाओं को लड़ाकू भूमिका की अनुमति दी गई है। सीआरपीएफ-सीआईएसएफ में कॉन्सटेबल के 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना में महिला आवेदकों के लिए प्राथमिकता तय की गई है। एकल मां के लिए पासपोर्ट के नियमों में भी केंद्र सरकार ने छूट तय की है।

2016 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शुरू किया गया। इसमें गर्भवती महिलाओं के लिए हर महीने की 9 तारीख को डॉक्टर द्वारा मुफ्त जांच की सुविधा है ताकि जच्चा-बच्चा की शुरू से ही सही देखभाल हो। इसका नतीजा है कि 2011-13 में मातृत्व मृत्यु दर जो प्रति लाख 167 थी वह 2015-17 में घटकर 122 पर आ गई। इसी तरह शिशु मृत्यु दर भी 28 से घटकर 22 फीसदी पर आ गई। इसी तरह प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना से 1.82 करोड महिलाओं ने लाभ उठाया।

महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सुरक्षित मातृत्व आश्वासन पहल, मिशन इंद्रधनुष, पोषण अभियान, किलकारी जैसी योजनाओं के जरिए महिलाओं को समय पर मातृत्व स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी, टीका, निर्देश और दवाई की सुविधा दिलाना है।

पीएम उज्ज्वला बना वरदान

लकड़ी से चूल्हे पर खाना पकाना एक कठिन काम ही नहीं बल्कि पर्यावरण के साथ-साथ महिला की सेहत पर भी असर पड़ता था। ऐसे

लाडो के लिए बढ़ती ललक

जब ब्रह्माजी ने सृष्टि का निर्माण कर लिया, तब उनके शरीर से मनु और शतरूपा पैदा हुए। बाद में इन दोनों के मिलन से पांच बच्चों का जन्म हुआ। इनमें तीन बेटियां थीं और दो बेटे थे। बेटियों के नाम थे आकूति, देवहुति और प्रसूति। बेटों के नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये पांच बच्चे दुनिया की पहली संतानें थीं। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि पहले पांच बच्चों में तीन बेटियां थीं। गरुड़ पुराण में वर्णित इस पौराणिक कथा का मतलब यही है कि प्रकृति और परमात्मा भी बेटियों को अधिक महत्व देते हैं। भगवान ने भी कभी बेटों और बेटियों में भेद नहीं किया है, ये भेद इंसानों ने बनाया है। यही कारण है कि शिक्षित समाज के साथ अब यह बंधन भी टूट रहा है। भ्रूण हत्या और नवजात बच्चियों को मारने या फेंक देने जैसी सामाजिक विकृति को देखकर समाज के एक वर्ग में चेतना का स्तर बढ़ा है, इसलिए संतानविहीन दंपती अब लड़कियां गोद लेकर नजीर पेश कर रहे हैं। वडोदरा के एक होटल में मैनेजर विवेक (बदला हुआ नाम) इसे सही मानते हैं। उन्होंने खुद गोद लेते समय बेटी को प्राथमिकता दी। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) के आंकड़े बताते हैं कि कैसे बड़े पैमाने पर लोगों के सोच में क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है. कारा के मुताबिक, 2015-16 में जहां भारतीय दंपतियों ने कुल 3011 बच्चों को गोद लिया। इनमें गोद लिए लड़कों की संख्या 1156 थी तो लड़कियों की संख्या 1855 थी। वर्ष 2019-20 तक यह आंकड़ा सतत रूप से बढ़ा ही है।

सिर्फ भारतीय दंपति ही नहीं बल्कि भारत से बच्चे गोद लेने वाले विदेशी दंपति भी गोद लेने के मामले में बेटियों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

भारतीय दंपति

वर्ष कुल	गोद लिए बच्चे	बेटे	बेटियां
2015-16	3011	1156	1855
2016-17	3773	1433	2340
2017-18	3823	1483	2340
2018-19	4027	1629	2398
2019-20	3745	1558	2187
2020-21*	2285	954	1331

(* आंकड़े 5 दिसंबर तक)

में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई है। पांच साल पहले देश में 55 फीसदी परिवारों में ही रसोई गैस पर खाना पकता था। लेकिन यह आंकड़ा 98 फीसदी पर पहुंच गया है। देश में 8 करोड़ गरीब परिवारों को इस योजना के तहत रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए हैं, जिसे सरकार 10 करोड़ तक पहुंचाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बताते हैं कि पारंपरिक ईंधन- लकड़ी, कोयला आदि से खाना पकाने से भारत में सालाना 5 लाख मौतें होती थी। लेकिन केंद्र सरकार के इस प्रयास से महिलाओं में सांस संबंधी बीमारी के मामलों में 20 फीसदी की कमी आई है।

खेल-विज्ञान में देश का गौरव बन रहीं महिला

खेल-कूद का क्षेत्र हो या एथलीट या फिर ज्ञान-विज्ञान का क्षेत्र, महिलाएं

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना की वजह से लैंगिक अनुपात बढ़ा है। वर्ष 2014-15 में 918 से बढ़कर यह वर्ष 2019-20 में प्रति हजार लड़कों के मुकाबले 934 हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से #selfieWithDaughter और #BharatKeeLaxmi जैसे कई अभियान चलाए गए, जिसने समाज की दशकों की धारणा बदल दी है।

95.06%

स्कूलों में महिला शौचालय हैं, इससे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाली बेटियों की संख्या अब कम हुई है।

- बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 19.72 लाख बेटियों को प्रोत्साहन दिया गया। अल्पसंख्यक समुदाय की 1.5 करोड़ बेटियों को 2,315 करोड़ रु. की स्कॉलरशिप दी गई है।
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के बाद सभी स्तर की शिक्षा में लड़कों के मुकाबले लड़कियों के नामांकन में बढ़ोतरी हुई है।
- सभी सरकारी स्कूलों में बेटियों को आत्मसुरक्षा की ट्रेनिंग देने की शुरुआत की गई।

405 जिलों में से 282 जिलों में 2014-15 के मुकाबले 2019-20 में लिंगानुपात में सुधार हुआ है।

5600 करोड़ रुपये के निर्भया फंड की स्थापना की गई। सभी थानों में महिलाओं की हेल्प डेस्क बनाने के लिए अलग से 100 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

निर्मला सीतारमण के रूप में पहली बार पूर्ण कालिक महिला रक्षा व वित्त मंत्री मिलीं तो मैकडॉनल्ड में काम कर चुकीं स्मृति ईरानी सबसे युवा महिला मंत्री के तौर सशक्तीकरण का प्रतीक बनीं।

अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। इस क्षेत्र में महिलाओं का प्रदर्शन लैंगिक समानता की मिसाल बन रहा है। केंद्र सरकार ने खेल में हर स्तर पर प्रतिभाओं को मौका देने के लिए आधारभूत संरचना तैयार की है तो 16 महिला टेकनोलॉजी पार्क इनोवेशन और विज्ञान को सीखने के लिए महिलाओं को नए अवसर दे रहे हैं। इस क्षेत्र में किरण स्कॉलरशिप चल रही है जो महिला वैज्ञानिकों की राह में आने वाली आर्थिक बाधाओं को दूर कर उन्हें समान अवसर मुहैया करा रही है।

सुरक्षित महिला, सशक्त राष्ट्र

वही समाज प्रगति कर सकता है जो महिलाओं का सम्मान करता हो। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा से लेकर स्वावलंबन बनाने की दिशा में बीते छह साल में सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं जिससे आधी आबादी को अपना हुनर दिखाने का सुरक्षित माहौल मिल रहा है। लंबे समय से

मांग थी कि महिलाओं के खिलाफ अपराध को संगीन मानते हुए कठोर सजा का प्रावधान किया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार ने भारतीय दंड संहिता में बदलाव करते हुए 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार पर कानून को सख्त बनाते हुए फांसी की सजा का प्रावधान किया तो 16 साल से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के मामले में सजा को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया। महिलाओं को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए भी जांच और ट्रायल को 2 महीने में पूरा करने का प्रावधान किया गया ताकि पीड़ित परिवारों और गवाहों को प्रभावित कर धमकाया न जा सके। हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए यूनीवर्सल हेल्पलाइन (181) शुरू की गई तो सरकारी और निजी कार्यस्थलों, मेट्रो और अन्य शहरों में भी महिला सुरक्षा के लिए 'शी-बॉक्स' बनाया गया। घरेलू हिंसा जैसे मामलों से निपटने के लिए वन स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं। दिसंबर 2020 तक 733 केंद्र देश के 730 जिलों में खोले जा चुके हैं। इनमें से 700 केंद्रों पर तीन लाख से ज्यादा महिलाओं के मामलों का समाधान किया गया। निर्भया फंड से देश में 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट, 100 करोड़ की लागत से महिला हेल्प डेस्क और 16 करोड़ की लागत से हिम्मत एप शुरू किया गया जो पुलिस और महिला के बीच एक सेतु का काम करता है। बालिकाओं और महिलाओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए संसद में बिल लाया गया जो यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे मामलों को तत्काल ट्रैक किया जा सके और न्याय मिले। इसके तहत जबरन मजदूरी, वेश्यावृत्ति, यौन शोषण, जबरन विवाह आदि के लिए सजा का प्रावधान है।

शिक्षित नारी: समाज का आधार

घर की नारी शिक्षित है तो पूरा परिवार शिक्षित हो सकता है। यह किसी भी मजबूत समाज की नींव होती है। केंद्र सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया और स्कूलों से लड़कियों के ड्रॉपआउट की समस्या का गहराई से अध्ययन किया। इसमें सरकार ने पाया कि स्कूलों में शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव और लड़कियों को आर्थिक बोझ मानने की सोच इसकी बड़ी वजह है। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अपने पहले संबोधन में ही स्वच्छता अभियान का एलान किया। इस अभियान में 11 करोड़ शौचालय ग्रामीण भारत में बनाए गए हैं, जिनमें से 4 लाख से ज्यादा शौचालय छात्राओं के लिए स्कूलों में बने। इससे ड्रॉपआउट दर में कमी आई है। छात्राओं के पंजीकरण 94 फीसदी से ज्यादा है, जबकि लड़कों का 89 फीसदी। लड़कियों को शिक्षित करने में केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली छात्रवृत्तियां, सुकन्या समृद्धि योजना ने लड़कियों को आर्थिक बोझ समझने की मानसिकता को भी कमजोर किया। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी लड़िकयां आगे आ रही हैं और 2014 के मुकाबले आईटीआई में दाखिला दोगुना हो गया है। विश्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि 2011 में जहां 59 फीसदी (15 साल से ऊपर) लड़कियां शिक्षित थी, जो 2018 में बढ़कर 66 फीसदी पहुंच चुकी थी।

कानून बनाकर तय की सुरक्षा

- 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म पर फांसी की सजा। दुष्कर्म के मामलों में 2 महीने में सुनवाई पूरी करने का कानून बनाया।
- मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने के लिए तीन तलाक की कुप्रथा को कानून बनाकर खत्म किया गया।
- महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों की पहचान के लिए नेशनल डेटा बेस बनाया। ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा रहे हैं।
- देश में 700 से अधिक वन स्टॉप सेंटर शुरू किए गए। कामकाजी महिलाओं के लिए कानून में अहम बदलाव किए गए।
- नई टैक्सी नीति के तहत हर टैक्सी में जीपीएस और पैनिक बटन अनिवार्य किए गए।
- पहली बार महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई। तीनों सेनाओं में स्थाई कमीशन की शुरुआत की गई।

महिलाओं के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों ने 350 से ज्यादा योजनाएं एक स्थान पर सुलभ कराने के उद्देश्य से 'नारी' पोर्टल की शुरुआत की है।

महिलाओं के आत्मसम्मान का अभियान

घर-घर शौचालय का निर्माण सिर्फ स्वच्छता का नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान का बड़ा अभियान बना है। आज देश के 6 लाख से ज्यादा गांव खुले में शौच से मुक्त है। सिर्फ शौचालय का निर्माण ही नहीं, पीएम आवास योजना के तहत संपत्ति में मालिकाना हक भी सुनिश्चित किया

स्वास्थ्य के साथ पोषण का विशेष ध्यान

महिला सुरक्षा के साथ स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 1 रुपये में सैनेटरी नैपकिन की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्रों से अब तक 7 करोड़ से ज्यादा सैनेटरी नैपकिन बेचे जा चुके हैं। सैनेटरी नेपकिन को जीएसटी फ्री किया गया है।

मिशन इंद्रधनुष के तहत 90 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। महिला स्वाभिमान के तहत स्वच्छ भारत मिशन द्वारा हर घर में शौचालय का निर्माण किया गया।

मातृत्व अवकाश 12 से बढ़ाकर 26 हफ्ते किया गया। कामकाजी महिलाओं के हर दफ्तर में पहली बार क्रेच(पालनाघर) की शुरुआत की गई।

पोषण अभियान के तहत वर्ष 2017 से अब तक 7,411 करोड़ रुपये दिए गए।

मातृ मृत्यु दर वर्ष 2015-17 के 122 के स्तर से घटकर वर्ष 2016-18 में 113 रह गई है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 1 करोड़ 82 लाख महिलाओं को 7849 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके खातों में दी जा चुकी है।

गवर्मेंट ई-मार्केट प्लेस(GEM) पोर्टल पर 32,000 से ज्यादा महिला उद्यमी रजिस्टर्ड हैं। लघु व मंझोले उद्योगों में भी महिलाओ की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई।

जा रहा है। 38 लाख से ज्यादा मकान पूरी तरह से महिलाओं के नाम पर बनाए गए हैं तो बाकी मकानों में 56 फीसदी पति-पत्नी के नाम पर साझा है। मुस्लिम महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी बनाकर वर्षों पुरानी कुप्रथा का अंत किया गया ताकि मुस्लिम महिलाएं आत्मसम्मान से जी सके। जम्मू-कश्मीर में गैर कश्मीरी से विवाह करने पर महिलाओं और उसके बच्चों को पैतृक संपत्ति के हक से वंचित कर दिया जाता था। लेकिन अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के बाद इस क्षेत्र की महिलाओं को उसका हक मिला है। प्रवासी भारतीयों द्वारा शादी करने और फिर छोड़ देने जैसे मामलों में भी कानून को सख्त बनाया गया।

सामाजिक सशक्तीकरण

सामाजिक धारणाओं की नई परिभाषा अब केंद्र सरकार की महिला केंद्रित पहल से मिलती है। महिलाओं को समान अवसर और समय मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने शारदा एक्ट- 1978 में बदलाव के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया है। जिसका काम विवाह की न्यूनतम उम्र क्या हो इसका निर्धारण करना है, अभी लड़कियों के विवाह के लिए 18 वर्ष न्यूनतम आयु का कानून है। हिंसा पीड़ित महिलाओं को राहत देने के मकसद से सरकार ने हाल ही में मेडिकल टर्मिनेशन प्रीगनेंसी एक्ट को मंजूरी दी है जिसमें गर्भपात के लिए समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। मातृत्व अवकाश की सीमा भी 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई है। सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ने की दिशा में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से सैनेटरी पैड का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी का कहना था, "गरीब बहन-बेटियों के बेहतर स्वास्थ्य की भी चिंता ये सरकार लगातार कर रही है। हमने जन-औषधि केंद्र के अंदर एक रूपये में सैनिटरी पैड पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। 6 हजार जन-औषधि केंद्रों में पिछले थोड़े से समय में करीब 5 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी पैड हमारी इन गरीब महिलाओं तक पहुंच चुके हैं।" आज महिलाएं स्वतंत्र है, आर्थिक रूप से सशक्त है, दृढ़ संकल्प से लैस है, सुरक्षा का भाव है और सिर्फ सपने देख नहीं रहीं, बल्कि उसे साकार भी कर रही हैं तो उसकी बड़ी वजह दशकों से चली आ रही लड़की या महिला को कमतर मानने की सोच में आया बदलाव है। अब लड़की के पैदा होने पर मायूसी के साथ 'लड़की हुई है' कहने वाले उत्साह के साथ कहने लगे हैं 'अरे वाह, घर में लक्ष्मी आई है।' महिला सशक्तीकरण की दिशा में इस नई सोच के बदलाव को आप इस तरह महसूस करिए। कल्पना कीजिए कि आप 130 करोड़ देशवासियों के चुने नेता हैं, जिसकी सोशल मीडिया पर बड़े प्रशंसक समूह हैं और आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट पूरी तरह से 7 महिलाओं को पूरे दिन के लिए सौंप देते हैं। कैसी अनुभूति होगी आपको। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर अपना ट्विटर अकाउंट 7 महिलाओं को सौंप दिया था। कथनी और करनी में साम्यता का यह अद्भूत उदाहरण ही दरअसल नए भारत के केंद्र में नारी शक्ति को समान अधिकार और अवसर दे रहा है, जहां महिलाएं भी सुरक्षा और सम्मान के साथ सशक्तीकरण की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं।●

अन्नदाता का सम्मान

70 साल से विकास की बाट जोह रहा देश का कृषि सेक्टर कोरोना काल में भी प्रगति की ओर बढ़ रहा है। कृषि क्षेत्र बेहतर हो और वर्ष 2022 में आजादी के 75वें पर्व तक देश के अन्नदाता की आय दोगुनी हो सके, केंद्र सरकार इसका सपना लेकर आगे बढ़ रही है। नई पीएम फसल योजना, कृषि कानून के साथ किसान रेल इसी दिशा में अहम कदम हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त भी जारी की।

किसान सम्मान निधि में एक बटन क्लिक से 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 18 हजार करोड़ रुपए से अधिक की अगली किस्त दिसंबर के अंतिम सप्ताह में पहुंच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में कहा कि इस योजना से अभी तक किसानों के खाते में 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में सरकार बनने के बाद नई अप्रोच के साथ काम शुरू किया। विश्वभर में कृषि में क्या बदलाव आए, क्या तरीके अपनाए गए, अर्थव्यवस्था के साथ कैसे जोड़ा, इसका अध्ययन कराया। खेती पर किसानों का खर्च कम करने के लिए सॉयल हेल्थ कार्ड, यूरिया की नीम कोटिंग, लाखों की संख्या में सोलर पंप लगाने का काम किया।

प्रधानमंत्री ने ये भी कहा

- किसानों के खेत में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा हो, इसके लिए दशकों पुरानी योजनाएं पूरी कराने के साथ 'पर ड्रॉप, मोर क्रॉप' के मंत्र पर माइक्रो इरिगेशन को भी बढ़ावा दे रहे हैं।
- स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से लागत का डेढ़ गुना एमएसपी करके फसलों की सूची बढ़ाई। देश में एक हजार से ज्यादा कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा। इनमें किसानों ने एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया है।
- देश के बैंकों का पैसा किसानों के काम आए इसके लिए 2014 में जहां 7 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान था, वो अब करीब 14 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया ताकि किसानों को कर्ज मिल सके। ढाई करोड़ छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा गया है।
- पंजाब सहित कई राज्यों में कांट्रैक्ट खेती सालों से हो रही है, एग्रीमेंट तोड़ने पर किसान पर जुर्माना लगता था लेकिन अब नए कानून में किसान पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
- नए कानून में यह भी साफ है कि एग्रीमेंट जिस रेट पर किया गया है, उतना तो फसल खराब होने पर भी देना ही होगा। अगर बाजार में माल महंगा बिका और फायदा अधिक हुआ तो किसान को बोनस भी मिलेगा।

पीएम फसल बीमा योजना
मामूली प्रीमियम पर मुसीबत के समय बड़ा बीमा कवच

एक साल में करीब 87 हजार करोड़ रुपए की क्लेम राशि किसानों को मिली। महाराष्ट्र के लातूर जिले के गणेश कहते हैं कि प्रधानमंत्री बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में करीब ढाई हजार रुपए का प्रीमियम दिया था लेकिन आपदा में फसल बर्बाद हुई तो करीब-करीब 54 हजार रुपए का भुगतान मिला। गणेश कोई ऐसे अकेले किसान नहीं हैं, बल्कि उनके जैसे मामूली प्रीमियम भुगतान करने वाले हजारों किसान आपदा के समय पीएमएफबीवाई का सुरक्षा कवच ले रहे हैं। मुसीबत के समय ये फसल बीमा उनके काम आया। पिछले एक साल में ही पीएमबीवाई में शामिल किसानों ने करीब 87 हजार करोड़ रुपए का बीमा क्लेम लिया है। करोड़ों किसानों को बीमा फसल योजना का लाभ मिल रहा है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान को जमीन से लेकर उत्पादित चीजों तक पर वित्तीय मदद और उनकी फसलों के लिए बीमा कवर लाभ दिया जाता है। ये मदद प्राकृतिक आपदाओं, कीड़े और बीमारी के कारण फसलों को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए दी जाती है। पहली बार कम से कम प्रीमियम से अधिक से अधिक सुरक्षा का लाभ देने का काम किया गया है। फरवरी, 2016 में लागू पीएमबीवाई योजना में दिसंबर, 2018 तक 1.42 करोड़ लोगों को लाभ मिला था जिसकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी, 2020 में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देते हुए कहा था, फसल बीमा योजना के तहत किसानों का व्यवस्था में विश्वास पैदा हुआ है।

इसलिए फसल बीमा योजना की जरूरत

देश में मोडिफाई नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम (एमएनएआईएस) 2010 से अस्तित्व में थी। लेकिन 2016 में जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लांच की गई तब तक आजादी के 67 साल बाद भी बड़े प्रीमियम के कारण सिर्फ 23 फीसदी किसान बीमा करवा रहे थे। किसानों को 2 फीसदी से 15 फीसदी तक प्रीमियम देना होता था। 16 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लांच की गई जिसमें बहुत कम प्रीमियम दर रखकर 50 फीसदी किसान बीमित करने का लक्ष्य रखा गया। इसमें प्रीमियम दर पर सीमा हटा दी गई। मौसम के हिसाब से खरीफ की फसल पर 2% और रवि की फसल पर 1.5% एक समान प्रीमियम दरें हैं। वार्षिक वाणिज्यिक और बागबानी की फसलों पर 5 फीसदी प्रीमियम है।

कौन ले सकता है योजना का लाभ और कैसे:-

इस योजना का लाभ वो सारे किसान उठा सकते हैं जो अधिसूचित भूमि पर अधिसूचित फसल का उत्पादन कर रहे हों। अपनी फसल का बीमा करवाया हुआ हो। ऋण लेने वाले किसानों के लिए ये बीमा लेना अनिवार्य है। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफ लाइन आवेदन बैंक या सामान्य सेवा केंद्र पर जाकर कर सकते हैं। फिर लिंक www.pmfby.gov.in पर स्टेटस जान सकते हैं।

फल-सब्जी ढुलाई में और बढ़ी आसानी, किसान रेल का शतक

किसानों के लिए एक और बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 28 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। यह रेल महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच रवाना की गई। भारतीय रेलवे ने पिछले साल 7 अगस्त को पहली किसान रेल की शुरूआत की थी। किसान रेल एक चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है। इसमें फल, दूध, सब्जी, मछली, मांस पूरी सुरक्षा के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है। पहले सड़क से ट्रांसपोर्टेशन के चलते किराया अधिक लगता था और समय भी अधिक लगता था। ऐसे में गांव में उगाने वाले और शहर में खाने वाले दोनों को ये महंगा पड़ता था। किसानों को किसान रेल के जरिए सामान ढुलाई के लिए सरकार करीब 50 फीसदी तक की सब्सिडी भी दे रही है, जिससे फायदा हो रहा है। ●

लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय

बच्चे के हाथ में खिलौना सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं होता, बल्कि उसके शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक विकास में भी इसका बड़ा योगदान होता है। लेकिन भारत में बिकने वाले खिलौनों में से मात्र 15 फीसदी खिलौने ही देश में बने होते हैं। यही नहीं, दुनिया के 7 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी मात्र 0.5 फीसदी है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान में अब खिलौना उद्योग को भी शामिल किया गया है।

हड़प्पा सभ्यता स्थलों की खुदाई में कई तरह के ऐसे खिलौने मिले हैं, जो उस काल में बच्चों के मानसिक विकास में अहम योगदान निभाते थे। देश की संस्कृति के साथ जीवन कौशल की झलक उस देश के खिलौनों में भी मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में खिलौना उत्पादन के द्वारा भारतीय संस्कृति के मर्म को जतलाने का आह्वान किया है। यह 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के प्रति खिलौना कारीगरों व उद्यमियों की जिज्ञासा को झकझोरने की पहल है। यह समय भारतीय खिलौनों के लिए वोकल होने का है।

ताकि खतरनाक खिलौनों से दूर रहें नौनिहाल...

खिलौने खतरनाक

विदेशों से आने वाले 66.9% खिलौने खतरनाक होते हैं। भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया) ने इस पर बाकायदा जांच कर एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की है।

भारत में 93 फीसदी खिलौने बाहर से मंगवाए जाते हैं। इनमें से कई के प्लांट चीन में हैं। रिपोर्ट के अनुसार छोटे बच्चों के लिए सही समझे जाने वाले साफ्ट टॉयज में थैलेट नाम का एक केमिकल होता है जो कैंसर का कारण बन सकता है।

इनमें से निकलने वाले रेशे, नाक, मुंह, गला और फेफड़ों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। जांच में लेड, आर्सेनिक जैसे खतरनाक हैवी मेटल भी खिलौनों में पाए गए।

इन पहल का फायदा क्या होगा

- भारत के स्थानीय खिलौना उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। नए रोजगार का सृजन होगा।
- स्थानीय खिलौनों के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा मिलेगा। बच्चों के मानसिक विकास में खिलौनों के महत्व को देखते हुए ही आंगनवाड़ी और स्कूलों को इससे जोड़ा गया है।
- बच्चों को अच्छी गुणवत्ता के खिलौने मिल सकेंगे, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर होंगे।

भारतीय खिलौनों की जरूरत क्यों?

केंद्र सरकार की खिलौना क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की पहल को समझने के लिए हमें दुनिया और भारत के खिलौना उद्योग के साथ बाजार को समझना चाहिए।

- मार्केट रिसर्च फर्म आईएमएआरसी के आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में खिलौनों का बाजार करीब 105 अरब डॉलर का है। इसमें से 85 फीसदी हिस्सेदारी चीन की है। उसके बाद यूरोप और अंत में श्रीलंका, मलेशिया व भारत का नंबर आता है।

7 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के इस विश्व बाजार में मात्र 0.5% खिलौने ही भारतीय होते हैं।

135 अरब डॉलर

पहुंच जाएगा विश्व बाजार 2029 तक खिलौनों का

भारत में खिलौनों का बाजार करीब 1.5 अरब डॉलर का है। वर्ष 2011 से 2018 के बीच इसमें करीब 15.9% की वृद्धि दर्ज की गई।

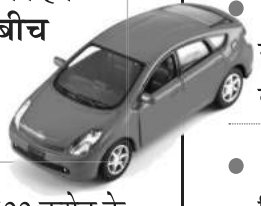

- भारत में 1 वर्ष में 3500 से 4500 करोड़ के खिलौने बेचे जाते हैं। लेकिन इसमें भारतीय खिलौना उद्योग की हिस्सेदारी वर्तमान में केवल 15%है, शेष 85 % बाजार पर बाहर से आयात होने वाले खिलौनों का कब्जा है।

केंद्र सरकार ने क्या पहल की हैं

4000

मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम कर रही भारत में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग सेक्टर के अंतर्गत, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग और वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार

75 प्रतिशत सूक्ष्म
22 प्रतिशत लघु व मध्यम
3 प्रतिशत बड़ी इकाइयां हैं।

टॉय फेयर जैसे आयोजनों के साथ भारतीय खिलौनों को नया मंच देने की कोशिश की जा रही।

- केंद्र सरकार दो तरफा पहल कर रही है। पहला, स्थानीय खिलौना उद्योग को बेहतर करने की और दूसरा, उन्हें उचित बाजार मिले इसके लिए भारतीय बाजार में मौजूद विदेशी खिलौनों से प्रतियोगता लायक माहौल देने की। इसके साथ भारतीय खिलौनों को बच्चों के स्वास्थ्य के लिहाज से भी बेहतर बनाया जा रहा है।
- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने इस क्षेत्र में भारतीय उद्योगों को पुनः स्थापित करने और भारत में मिलने वाले खिलौनों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय किए हैं।
- भारत में मिलने वाले खिलौनों की गुणवत्ता बेहतर हो इसके लिए भारत में बिकने वाले खिलौनों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेंडर्डज(बीआईएस) का सर्टिफिकेशन अनिवार्य किया गया है। साथ ही, नए आदेश के अनुसार भारत में बनने वाले हस्तशिल्प और जीआई खिलौनों को इसकी छूट रहेगी। विदेशी खिलौनों पर आयात शुल्क बढ़ाया गया है। ताकि भारतीय बाजार में भारतीय खिलौना उद्योग को सहारा मिल सके।

खिलौना क्लस्टर के तौर पर उभर रहे कर्नाटक के रामनगर के चन्नपटना, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कोंडापल्ली, तमिलनाडु के तंजावुर, असम के धुबरी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गौतमबुद्ध नगर जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश में अन्य जगह खिलौना उद्योग से संबंधित क्लस्टर के लिए जगह तलाशी जा रही हैं। भारतीय खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 14 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया है। इसके तहत एनसीईआरटी, सीबीएसई, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों द्वारा अगले 2-3 साल खिलौनों की थीम पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। एनसीईआरटी और अन्य नोडल अथॉरिटी को खिलौनों की लाइब्रेरी के साथ बच्चों को इतिहास, विज्ञान व गणित का बोध कराने वाले खिलौनों को शामिल करते हुए नया पाठ्यक्रम बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से इसे जोड़ा जाएगा। ताकि हमारे नौनिहालों के मानसिक और शारीरिक विकास में योगदान देने के साथ भारत का खिलौना उद्योग आत्मनिर्भर हो सके। ●

जमीन पर उतरने लगा

टीकाकरण का महाअभियान

नए साल में कोरोना से बचाव के लिए पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने की केंद्र सरकार की योजना अब जमीन पर उतारने की तैयारी पूरी, टीके की मंजूरी की प्रक्रिया पूरी होते ही दुनिया भर की उम्मीद भारत में पूरी होने लगेगी

इंतजार की घड़ी खत्म होने को है। कोरोना से निपटने में भारत की लड़ाई दुनिया के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बन गई है तो केंद्र सरकार भी टीके के विकसित होने और उसे अंतिम चरण में पहुंचाने में जुटे वैज्ञानिकों के साथ खड़ी है। कोवैक्सिन और कोवीशील्ड को आपात उपयोग के लिए मंजूरी मिलने के बाद लोगों तक पहुंचाने में तनिक भी देरी नहीं हो, इसकी भी पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार की ओर से हो रही है। टीके के विकसित होने, उसके उत्पादन से लेकर आम लोगों तक पहुंचाने की दिशा में सरकार ने अहम कदम बढ़ा दिया है।

कोविड वैक्सीन को लेकर ऑपरेशनल निर्देश जारी कर दिए गए हैं। टीका लगाए जाने के बाद 30 मिनट तक निगरानी की जाएगी। पहले चरण में करीब 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इसमें स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन कर्मचारी, 50 साल से उम्र के वे लोग जिन्हें कोई और भी बीमारी है, उन्हें प्राथमिकता वाले चरण में रखा गया है। इसके साथ ही, 50 साल से कम उम्र के भी उन लोगों को जो मधुमेह, कैंसर, दिल आदि बीमारियों से ग्रसित हैं, उन्हें भी इसी चरण में रखा गया है।

प्राथमिकता वाले चरण में इन 30 करोड़ लोगों को निःशुल्क लगाया जाएगा कोरोना का टीका

स्वास्थ्य कर्मी

स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले 1 करोड़ से अधिक निजी और सरकारी कर्मी शामिल।

फ्रंटलाइन कर्मचारी

राज्य एवं केंद्रीय पुलिस विभाग, तीनों सेनाएं, अर्ध सैनिक बल, होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा संगठन, निगम आदि के करीब 2 करोड़ कर्मचारी।

प्राथमिकता वाले आयु समूह

50 वर्ष की उम्र से अधिक तथा अन्य संवेदनशीलता वाले करीब 27 करोड़ लोग।

टीकाकरण की ये होगी प्रक्रिया और ऐसे लगेगा टीका

टीकाकरण के लिए पांच लोगों की टीम होगी, इन्हें वैक्सीनेटर ऑफिसर कहा जाएगा।

टीके के लिए ऐसे होगा पंजीकरण

- टीकाकरण के लिए पंजीकरण सिर्फ को-विन एप पर करने की तैयारी। केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा इसे अपलोड किया जा सकता है।
- अगर कोई व्यक्ति खुद से अपनी जानकारी अपलोड कर रहा है तो 15 दस्तावेज में से कोई भी उन्हें देना होगा।
- इसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्वास्थ्य बीमा, केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, पोस्ट ऑफिस की पासबुक, पेंशन दस्तावेज, सर्विस पहचान पत्र, वोटर कार्ड जैसी चीजें शामिल होंगी।
- राज्य सरकारों को टीकाकरण के लिए जरूरी तैयारी के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके लिए राज्य स्तर और जिला स्तर पर बनाई गई कमेटियों की बैठक भी हो चुकी है।

हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर का नि:शुल्क टीका

- देश में कोरोना टीका की तैयारी पूरी हो चुकी है। बस टीकाकरण शुरू किए जाने की तारीख आनी बाकी है। ऐसे में केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने टीका फैक्टरी से निकलकर लगाने तक की प्रक्रिया कैसे पूरी करेगी, इसे परखने का काम भी शुरू कर दिया है।
- जनवरी के पहले हफ्ते में पूरी मशीनरी ने मिलकर देशभर में कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन किया। ड्राई रन का मतलब कुछ यूं समझें कि वैक्सीन लगाने की पूरी प्रक्रिया की रिहर्सल हुई। इसमें ठीक उसी प्रक्रिया का पालन किया गया जो जो टीकाकरण के लिए अपनाई जाएगी।
- ऐसे ड्राई रन से पूरी प्रक्रिया की जांच की जा रही है कि जो मानक प्रक्रिया तय की गई है, वह सही से काम कर रहा है या नहीं?
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन के अनुसार चुनावी बूथ की टीम की तरह टीम को प्रशिक्षित किया गया है।
- प्रथम चरण में एक करोड़ हेल्थ केयर वर्कर और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण निशुल्क होगा।
- भारत बायोटेक की कोवैक्सिन और सीरम इंस्टिट्यूट की कोवीशील्ड को आपात उपयोग की मंजूरी मिल चुकी है।

जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं

अब तक कुल टेस्ट	96.19 %
17,56,35,761	रिकवरी दर

अब तक ठीक हुए मरीज- 99,46,867

सक्रिय मामले	कुल मरीज	कुल मौतें
2,43,953	1,03,41,416	1,50,858

(आंकड़े 4 जनवरी तक; स्रोत: स्वास्थ्य मंत्रालय)

कोरोना से निपटने की इस जंग में लॉकडाउन से पहले और बाद में अनलॉक की सोची-समझी तैयारी का ही नतीजा था कि भारत में सबसे सघन आबादी के बावजूद इसका प्रभाव दुनिया के मुकाबले कम हुआ। अब केंद्र सरकार की भविष्य के प्रति सोच और तैयारियों का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि टीकाकरण के बाद सीरींज और मेडिकल कचरा (वैस्ट) का कैसे निपटारा करना है, उसके लिए भी बाकायदा दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ●

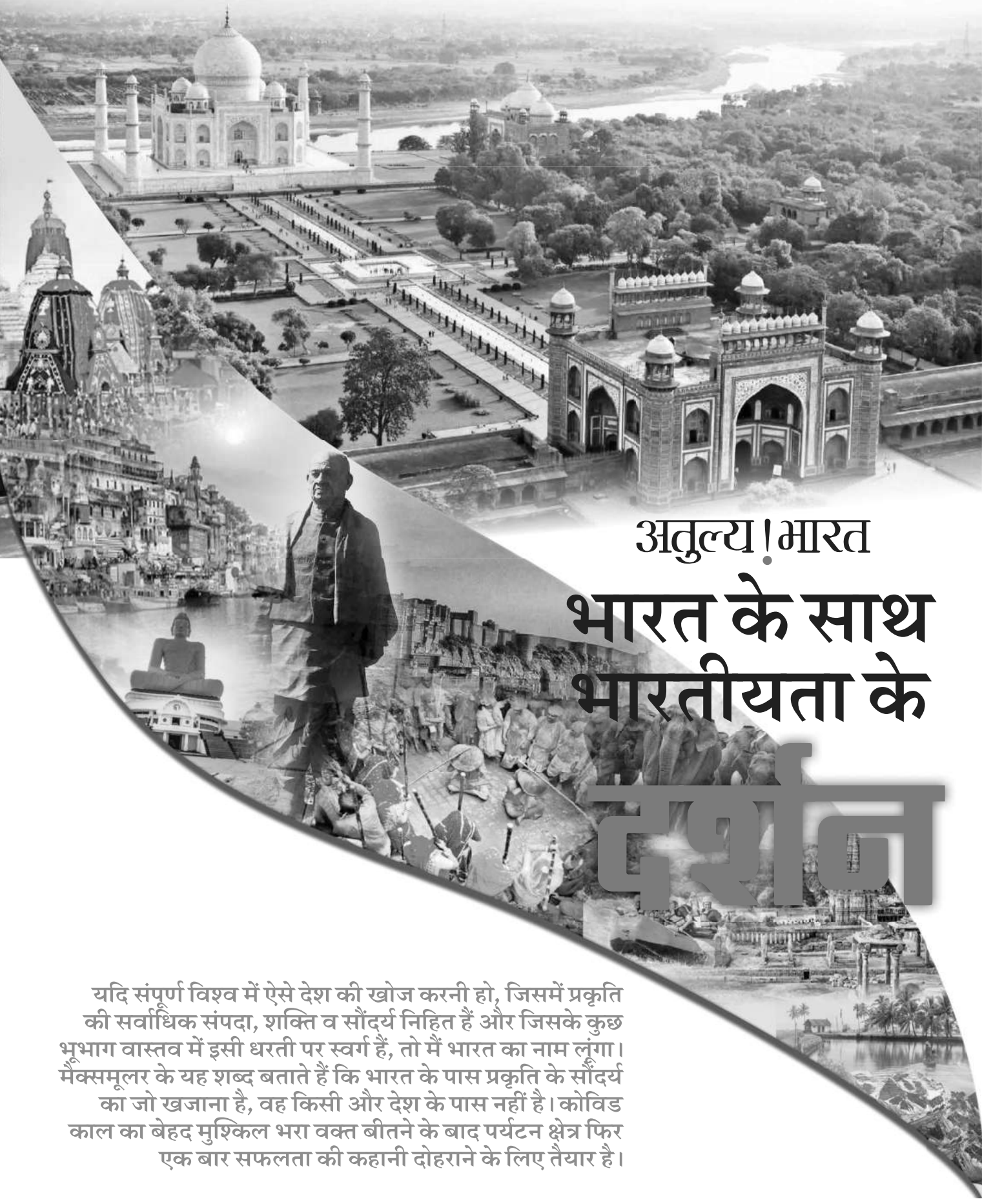

अतुल्य ! भारत

भारत के साथ भारतीयता के दर्शन

यदि संपूर्ण विश्व में ऐसे देश की खोज करनी हो, जिसमें प्रकृति की सर्वाधिक संपदा, शक्ति व सौंदर्य निहित हैं और जिसके कुछ भूभाग वास्तव में इसी धरती पर स्वर्ग हैं, तो मैं भारत का नाम लूंगा। मैक्समूलर के यह शब्द बताते हैं कि भारत के पास प्रकृति के सौंदर्य का जो खजाना है, वह किसी और देश के पास नहीं है। कोविड काल का बेहद मुश्किल भरा वक्त बीतने के बाद पर्यटन क्षेत्र फिर एक बार सफलता की कहानी दोहराने के लिए तैयार है।

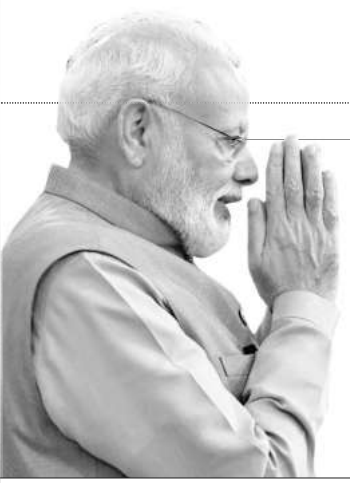

"ये बात सही है कि टूरिज्म सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। गरीब से गरीब व्यक्ति कमाता है और जब टूरिस्ट, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाता है। टूरिस्ट जाएगा तो कुछ न कुछ तो लेगा। अमीर होगा तो ज्यादा खर्चा करेगा और टूरिज्म के द्वारा बहुत रोजगार की संभावना है। विश्व की तुलना में भारत टूरिज्म में अभी बहुत पीछे है। लेकिन हम सवा सौ करोड़ देशवासी तय करें कि हमें अपने टूरिज्म को बल देना है तो हम दुनिया को आकर्षित कर सकते हैं। – नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री"

हिमालय की बर्फ से ढंकी वादियां, गोवा और केरल के समुद्र तट, दुनिया भर में प्रेम को प्रतीक ताजमहल, स्टेच्यू ऑफ यूनिटि के रूप में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, राजस्थान की गर्व करने वाली विरासत, मरुस्थल, धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर, 28 से ज्यादा विश्व विरासत स्थल, अभ्यारण्य और एक लंबी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और वास्तुकला की विरासत अपने भीतर जो देश समेटे होगा वो इस पर आखिर गर्व क्यों न करे? ऐसी विविधता अपने भीतर समेटे भारत दुनियाभर के देशों के बीच अकेला देश है। एक देश जहां हर औसत 15 किमी की दूरी पर बोली बदल जाती है। खान-पान बदल जाता है। हर दिशा अपने भीतर संस्कृति की विविधता के साथ विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता होने की अनुभूति समेटे हुए है। यही कारण है कि दक्षिण एशिया के कुल पर्यटन क्षेत्र में भारत का हिस्सा सबसे ज्यादा है। वर्ष 2020 में मुश्किल भरे वक्त के बाद जब हमारा पर्यटन क्षेत्र फिर से खड़े होने की कोशिश कर रहा है तब हमें याद रखना होगा कि 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था-" मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं। यह युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के लिए है, दुनिया में भारत की छवि बनाना है और दुनिया को यह बताना है कि भारत क्या करने में सक्षम है। यह समय है कि आप तय करें कि 2022 से पहले, जब भारत अपनी आजादी की 75 वां वर्षगांठ मना रहा होगा, हम अपने परिवार को देश के कम से कम 15 पर्यटन स्थलों पर ले जाएंगे।" यही नहीं, अमेरिका के ह्यूस्टन में आयोजित हाउडी मोदी कार्यक्रम में भी प्रवासी भारतीयों से प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल कम से कम पांच गैर भारतीय परिवारों को भारत में पर्यटन के लिए आने के लिए प्रेरित करने की अपील की थी।

भारत लगातार तरक्की कर रहा है और नए मुकाम हासिल कर रहा है। वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 140 देशों के बीच भारत 34वें स्थान पर है। वर्ष 2017 में भारत 40वें स्थान पर था, जबकि वर्ष 2013 में 65वें स्थान पर था। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार इसकी वजह प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधन के मामले में भारत का समृद्ध होना और कीमत के लिहाज से बेहद प्रतिस्पर्धी होना है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दक्षिण एशिया में सबसे प्रतिस्पर्धी यात्रा-पर्यटन अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

अर्थव्यवस्था में पर्यटन का अहम योगदान

- जीडीपी के लिहाज से भारत का पर्यटन क्षेत्र टॉप-10 सेक्टर में आता है।
- विदेशी धन का सबसे बड़ा स्रोत भी यही सेक्टर है। हाल के कुछ आंकड़ों पर गौर करें तो भारत के कुल रोजगार का करीब 13 फीसदी हिस्सा पर्यटन क्षेत्र का है।
- करीब 10 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी इस क्षेत्र में मिलता है।
- केंद्र सरकार ने बीते 6 वर्षों में भारत की सुंदरता, विविधता और वास्तुकला को सहेजने की दिशा में निरंतर प्रयास किए हैं।
- फिक्की की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पर्यटन क्षेत्र वर्ष 2029 तक 35 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है।

स्वदेश दर्शन के द्वारा प्रोत्साहन

विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने वाली अनेक योजनाओं को प्रारंभ करने के अतिरिक्त देशी पर्यटन को प्रोत्साहित करने और लोगों में अपनी विरासत के प्रति जागरुकता देने की दिशा में भी कई प्रयास किये गए हैं। इसके लिए सरकार ने 'स्वदेश दर्शन' नाम की योजना शुरू की है। केंद्र सरकार स्वदेश दर्शन की थीम पर टूरिस्ट सर्किट का विकास कर रही है। इसके तहत 13 सर्किट की पहचान की गई है- पूर्वोत्तर भारत सर्किट, बौद्ध सर्किट, हिमालयन सर्किट, तटीय सर्किट, कृष्णा सर्किट, मरुस्थल सर्किट, जन-जातीय सर्किट, इको सर्किट, वन्यजीव सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, रामायण सर्किट, और विरासत सर्किट। 73 परियोजनाओं के लिए कुल 5873.26 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है।

एडॉप्ट ए हैरिटेज : अपनी धरोहर, अपनी पहचान

इस योजना का उद्देश्य धरोहर स्थलों को विकसित करना और उन्हें योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से पर्यटकों के अनुकूल बनाना है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, निजी क्षेत्र की कंपनियों और नागरिकों / गैर सरकारी संगठनों / व्यक्तियों को जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।

बौद्ध सर्किट के विकास के लिए केंद्र सरकार ने विशेष प्रयास किए

- भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए स्थलों के महत्व को देखते हुए बौद्ध सर्किट के रूप में इनके विकास की शुरुआत की गई है।
- इसके माध्यम से सरकार का उद्देश्य गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा से पर्यटकों को अवगत कराना है।
- सरकार ने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश राज्यों को कवर करने वाले बौद्ध सर्किट थीम के तहत 355.26 करोड़ रुपए की पांच परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
- 24 जून 2020 को केन्द्रीय कैबिनेट ने बौद्ध सर्किट के अनिवार्य हिस्से के रूप में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया।

ई-वीजा समेत पर्यटकों के लिए कई सुविधाएं

- भारत अब 165 देशों के नागरिकों को ई-वीजा सुविधा दे रहा है। यह सुविधा 25 हवाई अड्डों और पांच बंदरगाहों पर मिल रही है।
- पर्यटकों की सुविधा के लिए 24 घंटे खुली रहने वाली बहुभाषी हेल्पलाइन की भी शुरूआत की गई है। ई-वीजा की वैधता की सीमा को भी 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दिया गया है।
- देश के 10 ऐतिहासिक स्थलों को देखने का समय बढ़ा दिया गया है और यह स्थल रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। इसके पहले ये दर्शनी स्थल आम जनता के लिए सुबह 9 बजे से शाम साढ़े 5 बजे तक खुले रहते थे।
- जनवरी-नवंबर 2019 के दौरान विदेशी पर्यटन आगमन (एफटीए) की संख्या 96,69,633 थी। वर्ष 2018 के मुकाबले यह 3.2 प्रतिशत ज्यादा है।
- जनवरी-नवंबर 2019 के दौरान 25,51,211 पर्यटक ई- वीजा पर भारत आए, जबकि जनवरी-नवंबर 2018 में यह संख्या 20,61,511 थी।

तीर्थयात्रा पर्यटन के लिए प्रसाद योजना

तीर्थयात्रा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योजना के तहत 25 राज्यों में विकास के लिए 41 स्थलों की पहचान कर 727.16 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इस योजना में देश में धार्मिक महत्व के अमरावती, अमृतसर, अजमेर, अयोध्या, बद्रीनाथ, द्वारका, देवघर, बेलूर, गया, गुरुवायुर, हजरतबल, कामाख्या, कांचीपुरम, कटरा, केदारनाथ, मथुरा, पटना, पुरी, श्रीसेलम, सोमनाथ, तिरुपति, त्रयंबकेश्वर, उज्जैन, वाराणसी और वेलानकनी को विकसित किया जा रहा है।

प्रवासी भारतीयों के लिए विशेष योजना

प्रवासी भारतीय अपने दिलों में भारत के लिए एक विशेष स्थान रखते हैं। भारत आने की उनकी प्रबल इच्छा को संतुष्ट करने और उन्हें विशेष आराम प्रदान करने के लिए सरकार ने प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना (पीटीडीवाई) और भारत को जानें (KIP) जैसे विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की है।

एक अन्य सेक्टर है जो विदेशी राशि मामले में शीर्ष पर है, वह है मेडिकल टूरिज्म। 2020 की रिपोर्टों के मुताबिक भारत का मेडिकल पर्यटन सेक्टर अनुमान के मुताबिक, 5-6 बिलियन का है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका से भी अच्छी खासी संख्या में मेडिकल पर्यटक भारत आते हैं। सरकार ने फरवरी 2019 में मेडिकल वीजा को शामिल करते हुए अपने ई-टूरिज्म वीजा व्यवस्था का विस्तार किया। इसके तहत ठहरने की अधिकतम अवधि छह महीना है। 30 अगस्त 2019 से विदेशी बिना मेडिकल वीजा के अंग प्रत्यारोपण को छोड़कर भारत में कोई भी चिकित्सा उपचार करा सकता है।

बीते 6 साल में केंद्र सरकार के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि दुनियाभर के पर्यटकों के बीच भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है और कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित रहा यह सेक्टर एक बार फिर उड़ान भरने को तैयार है। ●

समतामूलक समाज के निर्माण में केंद्र का छात्रों के लिए अभूतपूर्व कदम

सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मूलमंत्र के साथ कैबिनेट ने अनुसूचित जाति के 4 करोड़ से ज्यादा छात्रों को संबल देने और गांव-गरीब तक डीटीएच सेवा का विस्तार करने के लिए उठाए कदम तो अन्नदाता के हक में अनाज से एथनॉल को निकालने के प्रस्ताव को दी मंजूरी...

● फैसला: **अनुसूचित जातियों के छात्रों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में केंद्र की भागीदारी को 5 गुना बढ़ाया गया। 59 हजार करोड़ से अधिक की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी।**

● **प्रभाव:** इस पर ध्यान केंद्रित करने से ड्रॉपआउट दर में कमी आएगी। 5 साल में 4 करोड़ से ज्यादा छात्रों को लाभ मिलेगा। एक विशेष अभियान चलाकर 1.36 करोड़ बेहद गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा में अगले पांच साल में नामित किया जाएगा।

● छात्रवृत्ति में 60% हिस्सा केंद्र डीबीटी से छात्र के खाते में भेजेगा। 11वीं के बाद के सभी कोर्स के लिए छात्रवृत्ति में पूरी ट्यूशन फीस, मासिक मेनटेनेंस का भत्ता आदि शामिल है।

● फैसला: **दिल्ली के अनाधिकृत कॉलनियों को अदालती मामलों से बचाने के लिए कानूनी संरक्षण को तीन साल के लिए बढ़ाया गया।**

● **प्रभाव:** मिनी इंडिया मानी जाने वाली राजधानी दिल्ली जहां देश के कई राज्यों के लोग रहते हैं। ऐसे लाखों लोगों को संरक्षण देने के लिए 2011 में कानून बना था जो 2014 में समाप्त हुआ। मोदी सरकार ने इसे तीन साल के लिए आगे बढ़ाया था। इसके लिए अध्यादेश जारी किया गया है। पिछले साल 1700 अनाधिकृत कॉलनी में रहने वाले 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देने का ऐतिहासिक फैसला केंद्र सरकार ने किया था।

● **फैसला: अनाज से एथनॉल का प्रस्ताव मंजूर**

● **प्रभाव:** गन्ने के बाद अब गेहूं, चावल, मक्का और अन्य खाद्यान्न से भी एथनॉल उत्पादन की मंजूरी दे दी गई है, ताकि बाजार में कृषि उपज का अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके। देश में पहली पीढ़ी एथनॉल के उत्पादन के लिए संशोधित योजना के तहत अनाज (चावल, गेहूं, जौ, मक्का और शर्बत), गन्ना, चीनी पत्ता आदि से एथनॉल का उत्पादन किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने इथेनॉल उत्पादन संयंत्रों के लिए 4,573 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद को भी मंजूरी दी।

● **फैसला: डीटीएच सेवाएं प्रदान करने के दिशा-निर्देश में संशोधन को मंजूरी।**

● **प्रभाव:** देशभर के 18 करोड़ टीवी में से 6 करोड़ से डीटीएच से जुड़े हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने 100% एफडीआई का निर्णय किया था। ये लागू नहीं हो पा रहा था। अब वैसी ही गाइडलाइन से 100% के दायरे में ये क्षेत्र भी होंगे। ट्राइ से विचार विमर्श करके विसंगति दूर की गई। लाइसेंस अब 20 साल व नवीनीकरण दो साल का होगा।

इसके अतिरिक्त केंद्रीय कैबिनेट ने ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के तहत कृष्णपत्तनम और तुमाकुरू में औद्योगिक गलियारे को मंजूरी दी है। दो ट्रेड कॉरिडोर बनने से माल ढुलाई अच्छे से होगी। इस कॉरिडोर के साथ जहां एक्सप्रेस-वे हैं, बंदरगाह हैं, रेलवे की सुविधा है और एयरपोर्ट भी हैं। गुजरात के पारदीप में भी 3000 करोड़ रुपये की लागत से विश्व स्तरीय बंदरगाह बनाने कर मंजूरी दी गई है। इसके साथ 5 बिलियन डॉलर के रक्षा निर्यात का लक्ष्य पूरा करने के लिए आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात को मंजूरी दी गई है। ●

देश के पहले परमवीर मेजर सोमनाथ शर्मा

31 जनवरी को उस शहीद सैनिक की जयंती है, जिन्हें अद्भूत पराक्रम और वीरता के लिए देश के सबसे पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 1950 में पहली बार देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र देने की शुरुआत हुई थी। भारतीय सेना ने इस सबसे बड़े सम्मान के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा को चुना...

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में 1923 में जन्मे मेजर सोमनाथ शर्मा ने 1942 में रॉयल मिलिट्री कॉलेज से स्नातक किया। पिता, दोनों भाई, दोनों बहनें आर्मी में थे। खून में ही वीरता थी तो शर्मा भी सेना में ही शामिल हो गए। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रहते हुए उन्होंने बर्मा में दूसरे विश्वयुद्ध में हिस्सा लिया। उनका फौजी कार्यकाल शुरू ही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ। पहले ही दौर में इन्होंने अपने पराक्रम के तेवर दिखाए और वह एक विशिष्ट सैनिक के रूप में पहचाने जाने लगे।

स्थान: बडगाम(कश्मीर)

समय: 3 नवंबर 1947

हाथ में प्लास्टर फिर भी जंग के मैदान में कूद पड़े

बंटबारे के बाद 22 अक्टूबर, 1947 को जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया तब हॉकी खेलते हुए बांया हाथ टूट जाने की वजह से सोमनाथ इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें जब पता चला कि उनकी बटालियन युद्ध के लिए कश्मीर जा रही है, तो उन्होंने उसका हिस्सा बनने की जिद शुरु कर दी। सोमनाथ की जिद आगे सीनियर अधिकारियों को भी मानना पड़ा। सोमनाथ शर्मा कुमाऊं रेजिमेंट की चौथी बटालियन की डेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर थे।

3 नवंबर 1947 को बडगाम में सेना की 3 कंपनियां तैनात की गई। उन्हें उत्तर की तरफ से बढ़ने वाले पाकिस्तानी सैनिकों को श्रीनगर पहुंचने से रोकना था। करीब 700 आतंकियों और पाकिस्तानी सैनिकों की एक टुकड़ी बडगाम की तरफ बढ़ी। मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी तीन तरफ से दुश्मनों से घिर गई। एक हाथ पर प्लास्टर चढ़े होने के बावजूद वो तीन सैन्य टुकड़ियों के हमले का संचालन संभाल रहे थे। मेजर सोमनाथ शर्मा खुद भाग-भागकर सैनिकों के बीच हथियार और गोला-बारूद की सप्लाई कर रहे थे। एक लाइट मशीनगन उन्होंने अपने हाथ में थाम रखी थी।

इसी दौरान आतंकियों का एक मोटार्र शेल गोल-बारूद के एक जखीरे पर गिरा। इसमें मेजर सोमनाथ शर्मा वीरगति को प्राप्त हुए। शहीद होने से पहले उन्होंने अपने हेडक्वॉर्टर को संदेश भेजा था दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर हैं, हमारी संख्या काफी कम है, हम भयानक हमले की जद में हैं, लेकिन हमने एक इंच जमीन नहीं छोड़ी है, हम अपने आखिरी सैनिक और आखिरी सांस तक लड़ेंगे।' 3 दिन बाद मिले उनके शव की पहचान उनके पिस्टल के होल्डर और उनके सीने से चिपकी भगवत गीता से हुई। ●

भरोसा जीतने में सफल हो रही हैं योजनाएं

पहले जब लोगों को न्याय और उन्हें फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलता था तो वह किस्मत को ही दोषी मानते थे। हालांकि, अब ऐसा नहीं है। सरकार की योजनाओं और कानून से अब लोगों के जीवन में बदलाव आ रहे हैं।

घरेलू हिंसा की शिकार महिला को मिला न्याय

साल 2017 में शुरू किए जाने के बाद से टेली-लॉ आम लोगों को तेजी से न्याय मुहैया कराने का एक लोकप्रिय मंच बन कर उभरा है। यह सेवा देश के 260 जिलों और 29860 सामुदायिक सेवा केन्द्रों में चल रही है। इसके जरिए देश के सुदूर और दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले 2.75 लाख से अधिक लाभार्थियों को टेलीफोन और वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कानूनी सहायता मिल रही है। ऐसी ही एक महिला हैं सैयदा रिजवी जिन्हें सरकार की टेली-लॉ योजना से लाभ मिला। जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले के गुंडीपोरा गांव की रहने वाली सैयदा को बच्चा नहीं हो रहा था सो उसके ससुराल वाले उसके साथ मारपीट और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। एक बार वह दो दिन तक एक कमरे में बंद रही। वहां से बच निकलने के बाद वह अपने माता-पिता के पास आ गई। वहां एक आशा कार्यकर्ता ने उसे टेली-लॉ के बारे में जानकारी दी। सैयदा ने टेली-लॉ की मदद से शिकायत दर्ज कराई। इस मामले को एक महीने के अंदर सुलझा लिया गया और सैयदा के पति ने अपना दोष स्वीकार कर लिया।

नए कृषि कानून से हुआ किसान का फायदा

हाल में बिहार के समस्तीपुर जिले के एक किसान की कहानी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रही। इस जिले के एक किसान की गोभी की फसल बहुत कम कीमत में बिक रही थी। हालांकि, जब यह बात किसी तरह कॉमन सर्विस सेन्टर तक पहुंची तब इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उस किसान को गोभी की फसल खरीद के लिए दिल्ली के एक व्यापारी ने दस गुना दाम देने का प्रस्ताव रखा। दरअसल, केन्द्र सरकार ने किसानों की फसल बेचने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। यानी जो गोभी पहले एक रुपए किलो बिक रही थी वो अब दस रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकने जा रही थी। किसान की सहमति के बाद खरीददार ने कुछ ही घंटे में किसान के खाते में एडवांस रुपए भेज दिए। दरअसल, ऐसा केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के कारण संभव हो सका। इस कानून की मदद से किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं। समस्तीपुर के गोभी किसान की कहानी इसका एक जीता-जागता उदाहरण है।

"आइए, हम नये साल पर 'वोकल फॉर लोकल' का संकल्प लें"

21वीं सदी की ऐतिहासिक आर्थिक घटना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 के आखिरी 'मन की बात' कार्यक्रम में देश की जनता से स्थानीय उत्पादों को अपनाने और देश को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने सिख गुरुओं को उनकी वीरता और बलिदान के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत में तेंदुओं की संख्या में वृद्धि, युवाओं से जुड़ी प्रेरक कहानियां, कश्मीर के केसर को जीआई टैग मान्यता के अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने की भी बात की। पेश हैं 'मन की बात' के अंश:

- नए साल का संकल्प: 2021 की शुरुआत होने जा रही है। मेरे सामने आपकी लिखी ढेर सारी चिट्ठियाँ हैं। ज्यादातर संदेशों में, बीते हुए वर्ष के अनुभव, और, 2021 से जुड़े संकल्प हैं। चुनौतियों के बीच देश में आए बदलाव को भी लोगों ने महसूस किया है। हमने हर संकट से नए सबक लिए। देश में नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ। इस सामर्थ्य का नाम है- 'आत्मनिर्भरता।'
- मेड इन इंडिया बना गौरव: पहले खिलौनों का मतलब इंपोर्टेड खिलौना होता था, लेकिन अब दुकानदार खिलौनों की अच्छी क्वालिटी का बताकर बेच रहे हैं, क्योंकि यह मेड इन इंडिया है। मैं देश के मैन्युफैक्चरर्स इंडस्ट्री लीडर्स और देश के लोगों से आग्रह करता हूं कि वे वोकल फॉर लोकल की तरफ बढ़ें और विश्वस्तरीय मानदंडों को सुनिश्चित करें।
- आत्मनिर्भर भारत की ABC: मुझे विशाखापत्तनम से वेंकट मुरलीप्रसाद जी ने जो लिखा है, उसमें भी एक अलग ही तरह का आइडिया है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में 2021 के लिए ABC चार्ट भेजा है यानी आत्मनिर्भर भारत चार्ट। इसमें उन सभी चीजों की पूरी सूची है जिन्हें वो रोजाना इस्तेमाल करते हैं। 'वोकल फॉर लोकल' आज घर-घर में गूंज रहा है।
- गुरु गोबिंद सिंह और महान गुरु परंपरा: हम श्री गुरू तेग बहादुर जी, गुरू गोबिंद सिंह जी और चारों साहिबजादों के कर्जदार हैं। ऐसी ही अनेकों शहादतों ने भारत के आज के स्वरूप को बचाए रखा है, बनाए रखा है।
- तेंदुओं की संख्या बढ़ी: भारत में तेंदुओं की संख्या में 2014 से 2018 के बीच, 60 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। पिछले कुछ सालों में, भारत में शेरों की आबादी बढ़ी है, बाघों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, साथ ही, भारतीय वनक्षेत्र में भी इजाफा हुआ है।
- संवेदनशीलता: हम सबने इंसानों वाली व्हीलचेयर देखी है, लेकिन कोयंबटूर की एक बेटी गायत्री ने अपने पिताजी के साथ कुत्ते के लिए व्हीलचेयर बना दी। ये संवेदनशीलता प्रेरणा देने वाली है। कौशांबी जेल में बंद कैदी पुराने कंबलों से गाय को ठंड से बचाने के लिए कवर बना रहे हैं।
- युवा ब्रिगेड का संकल्प: जब मैं भारत के युवाओं को देखता हूं तो खुद को आनंदित और आश्वस्त महसूस करता हूं क्योंकि मेरे देश के युवाओं में 'CAN DO' का दृष्टिकोण है और 'WILL DO' की भावना है।
- कश्मीरी केसर को जीआई टैग: जीआई टैग प्राप्त करने के बाद कश्मीरी केसर को दुबई के एक सुपरमार्केट में लांच किया गया। इससे आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमारे प्रयासों को और बल मिलता है।
- सिंगल यूज प्लाटिस्क से मुक्ति: सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए नए साल में हमें ये संकल्प भी लेना चाहिए कि हम कचरा फैलाएंगे ही नहीं, आखिर, स्वच्छ भारत अभियान का भी तो पहला संकल्प यही है।

'मन की बात' पूरी सुनने के लिए QR कोड Scan करें

Narendra Modi @narendramodi

साल 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थीं, चारों तरफ सवालिया निशान थे। 2020 की वह पहचान बन गई, लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर आ रहा है।

मुझे विश्वास है कि जिस तरह बीते साल संक्रमण रोकने के लिए हमने एकजुट होकर प्रयास किए, उसी तरह टीकाकरण को सफल बनाने के लिए भी देश आगे बढ़ेगा।

Rajnath Singh @rajnathsingh

वर्षों तक देश के लिए अपनी जवानी कुर्बान करने वाले पूर्व सैनिक प्रतीक्षा करते रहे कि सरकार उन्हें One Rank One Pension का हक देगी।

प्रधानमंत्री श्री @narendramodi ने सत्ता में आने के बाद देश की जनता से किया हुआ अपना वादा निभाया और OROP देकर देश के पूर्व सैनिकों को उनका हक दिया।

Amit Shah @AmitShah · 25 Dec 20

गत 6 वर्षों से मोदी सरकार ने अपना हर निर्णय देश के गरीबों, किसानों और वंचितों को केंद्र में रख कर लिया है। जिससे उन्हें उनका अधिकार मिला और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आये।
#PMKisan भी एक ऐसी ही अभूतपूर्व योजना है जिससे मोदी जी हर वर्ष किसानों के खातों में ₹6000 भेजते हैं।

Nitin Gadkari @nitin_gadkari

राज्य में निर्माणाधीन परियोजनाओं के साथ भविष्य में नियोजित परियोजनाओं में से 50 हजार करोड़ की कुल 22 परियोजनाओं की आज घोषणा की। इन परियोजनाओं पर जल्द ही काम शुरू होने का आश्वासन दिया।

Translate Tweet

Smriti Z Irani @smritiirani

प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने के बाद लखीमपुर खेरी की बुजुर्ग महिला ने गाने के माध्यम से उन्हें शतायु होने का आशीर्वाद दे रही हैं। यशस्वी PM @narendramodi जी के प्रति देशवासियों का यह स्नेह और समर्थन अभूतपूर्व है।

Dr Harsh Vardhan

#CovidVaccine तैयार, आख़िरी प्रहार का इंतज़ार !

जिस तरह चुनाव के समय प्रत्येक बूथ पर तैनात कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से health workers को भी प्रशिक्षण दिया गया है।

#vaccination के लिए विस्तृत guidelines भी तैयार करी गई हैं।

कश्मीरी केसर को जीआई टैग से मिली खास पहचान : मोदी

मन की बात में बोले पीएम...निर्यात से आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी मजबूती

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिलने से उसे एक खास पहचान मिली है और केंद्र सरकार इसे वैश्विक स्तर पर

गुरुग्राम के प्रदीप और कर्नाटक के दंपती के स्वच्छता प्रयासों को सराहा

पीएम ने गुरुग्राम के रहने वाले प्रदीप सांगवान और कर्नाटक के दंपती अनुदीप व मिनूषा के स्वच्छता प्रयासों की सराहना की। कहा, प्रदीप हीलिंग हिमालय नामक अभियान चला रहे हैं। हिमालय के अलग अलग स्थानों पर जाते हैं और पर्यटक जो कचरा छोड़कर जाते हैं, उसे साफ करते हैं। वह

मन की बात: प्रधानमंत्री ने कहा- वोकल फॉर लोकल आज हर घर का मंत्र बना

भारत में बने उत्पादों के प्रयोग का संकल्प लें: मोदी

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले विदेश में निर्मित वस्तुओं के विकल्प के रूप में मौजूद भारतीय उत्पादों को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोगों को इसे नव वर्ष के संकल्प के तौर पर लेना चाहिए।

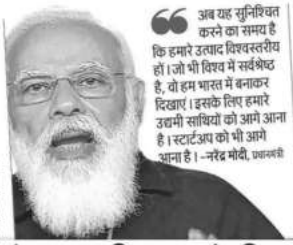

देशवासियों का साथ मिला : रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 72वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत वोकल फॉर लोकल के मंत्र को देश की

अब यह सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे उत्पाद विश्वस्तरीय हों। जो भी विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, वो हम भारत में बनाकर दिखाएं। इसके लिए हमारे उद्यमी साथियों को आगे आना है। स्टार्टअप को भी आगे आना है। –नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

सिख गुरुओं को नमन

मोदी ने कहा, आज के ही दिन गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। अत्याचारी चाहते थे कि साहिबजादे महान गुरु परंपरा की सीख छोड़ दें। पर उन्होंने कम उम्र में गजब का साहस दिखाया। गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार द्वारा दी गई शहादत ने मानवता को सीख दी।

गीता हमारे जीवन की प्रेरणा

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, गीता हमें हमारे जीवन के हर संदर्भ में प्रेरणा देती है। यह गीता की विशिष्टता भी है। ये जानने की जिज्ञासा से शुरू होती है और जब तक जिज्ञासा है, तब तक जीवन है। गीता की ही तरह, हमारी संस्कृति में जितना भी ज्ञान है, सब जिज्ञासा से ही शुरू होता है।

'मन की बात' में गीता, गुरु गोबिंद और केसर की बात

■भाषा, नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आकाशवाणी पर प्रसारित कार्यक्रम 'मन की बात' के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। यह इस कार्यक्रम का 72वां और 2020 का आखिरी संस्करण था। इस दौरान पीएम ने कश्मीर के केसर के साथ ही गीता और गुरु गोबिंद सिंह की भी चर्चा की।

पीएम ने कहा, ऐसा कहते हैं कि अकबर के दरबार में एक प्रमुख सदस्य अबुल फजल थे। उन्होंने एक बार कश्मीर की यात्रा के बाद कहा था कि कश्मीर में

इसके साथ ही पीएम ने कहा कि जब तक जिज्ञासा है, तब तक जीवन है। वेदांत का तो पहला मंत्र ही है – 'अथातो ब्रह्म जिज्ञासा' अर्थात, आओ हम ब्रह्म की जिज्ञासा करें। क्या आपने कभी सोचा

हर गांव को सड़क से जोड़ने का पीएम मोदी का सपना साकार करने में जुटी सरकार

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को तवज्जो, राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता

1872 बस्तियों को सड़कों को जोड़े जाने का लक्ष्य

मैदानी क्षेत्रों में 500 और पर्वतीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी को सड़कों से जोड़ा जाना था।

42 योजना क्रियान्वयन इकाइयों की मदद से वर्तमान में इस काम को अंजाम दिया जा रहा है।

508 करोड़ से बनेंगी सड़कें और पुल, दो साल में काम होगा पूरा

मसूरी में बनेगी टनल जाम से मिलेगी निजात

त्यूनी- टिहरी-मलेथा मार्ग होगा डबल लेन

सड़क संयोजकता को बढ़ाने में लगाई ताकत

साढ़े तीन साल में कमाल फैलाया सड़कों का जाल

2133

आर.एन.आई
DELHIN/2020/78812
16 से 31 जनवरी, 2021

न्यू इंडिया
समाचार
पाक्षिक

आरएनआई DELHIN/2020/78812, दिल्ली पोस्टल लाइसेंस नंबर -
DL (S)-1/3550/2020-22 डब्ल्यूपीपी संख्या U (S)-98/2020-22, posting at BPC,
Meghdoot Bhawan, New Delhi - 110 001 on 13-17 advance Fortnightly
(प्रकाशन तिथि - 8 जनवरी 2021, कुल पृष्ठ-40)

पंजाब केसरी लाला लाजपत राय

जन्म: 28 जनवरी 1865 | मृत्यु: 17 नवंबर 1928

“पंजाब केसरी लाला लाजपत राय एक अनूठी शख्सियत थे जो अपने समय से आगे थे। मैं भारत के इस महान सपूत की जयंती पर उन्हें सलाम करता हूं।
नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री”

संपादक:
कुलदीप सिंह धतवालिया, प्रधान महानिदेशक,
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

प्रकाशक और मुद्रक:
सत्येन्द्र प्रकाश महानिदेशक, बीओसी
(ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन)

ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन,
सूचना भवन, द्वितीय तल, नई दिल्ली-
110003 से प्रकाशित

मुद्रण: जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्राइवेट
लिमिटेड, बी-278, ओखला इंडस्ट्रियल
एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-20